सांध्य दैनिक

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534

डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 261 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शनिवार 04 जुलाई 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

रायपुर में सोलर पैनल लगा रहे हाईटेंशन की चपेट में आए, दो की मौत

रायपुर। राजधानी के प्रोफेसर कॉलोनी इलाके में शनिवार को सोलर पैनल लगाते समय छत पर काम कर रहे दो मजदूर हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुरानी बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतकों का नाम पुलिस द्वारा प्रमोद चंद्राकर (25) और आशीष चंद्राकर (19) बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया सोलर पैनल लगाने के दौरान एक उपकरण पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। तेज करंट लगते ही दो मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। दो मजदूरों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। तीसरा मजदूर बाल-बाल बच गया।

ब्रह्मपुर-उधना के बीच चलेगी अमृत भारत स्पेशल ट्रेन

रायपुर। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल द्वारा ट्रेन संख्या 08411 ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस स्पेशल का पहली बार संचालन किया जा रहा है। यह विशेष ट्रेन ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात के यात्रियों को सीधी एवं सुविधाजनक रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। अमृत भारत एक्सप्रेस आधुनिक एलएचबी कोचों से सुसज्जित है। गाड़ी संख्या 08411 ब्रह्मपुर-उधना ब्रह्मपुर स्टेशन से 17.00 बजे रवाना होकर विजयनगरम -टिटलागढ़ होते हुए रायपुर 7:20 बजे, दुर्ग 8:15 बजे, गोंदिया 8.25 बजे, नागपुर 12:00 बजे होते हुए अकोला भुसावल के रास्ते से उधना 2:00 बजे पहुंचेगी। इसे 6 जुलाई 2026 को शाम 17:00 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।

मानसून के चलते तापमान में 3-5 डिग्री की गिरावट

रायपुर। प्रदेश में बीते दो-तीन दिनों से हो रही अच्छी बारिश के कारण रायपुर समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री तक नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को सारंगढ़ में सर्वाधिक 140 मिमी वर्षा हुई। शुक्रवार को अंबिकापुर में दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक तापमान रहा। जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री पेंड्रारोड में रिकॉर्ड किया गया।

धमतरी जिला प्रशासन की अनूठी 'पहल', प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिलेगी मुफ्त कोचिंग

श्रीकंचनपथ न्यूज

धमतरी। जिला प्रशासन ने एक बेहद सराहनीय और दूरदर्शी कदम उठाते हुए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पहल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस विशेष योजना के तहत जिले के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इस अवसर पर विद्यार्थियों के सही मार्गदर्शन के लिए 'युवा' नामक एक विशेष पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने इसे युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य उन होनहार युवाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर देना है, जो आर्थिक तंगी के कारण महंगी कोचिंग संस्थानों का खर्च नहीं उठा पाते। इस निःशुल्क कोचिंग के जरिए विद्यार्थियों का बेसिक फाउंडेशन मजबूत होगा, जिससे वे हर प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का परचम लहरा सकेंगे।

जानिए क्या है 'युवा' प्रोजेक्ट और इसकी खासियतें?

प्रशासन की यह मुहिम केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि छात्रों की पूरी तैयारी को व्यवस्थित और परिणामोन्मुख बनाने के लिए एक मुकम्मल खाका तैयार किया गया है।कोचिंग में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को बेहतरीन बुक्स और स्टडी मटेरियल मुफ्त दिया जाएगा। तैयारी के स्तर को जांचने और उसमें सुधार करने के लिए समय-समय पर टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। छात्रों के प्रदर्शन की निरंतर समीक्षा की जाएगी, ताकि उनकी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें समय पर सुधारा जा सके। इस भव्य शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बीसीएस कॉलेज के प्राचार्य, उप संचालक पंचायत, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, सहायक संचालक कौशल विकास, युवाओं को प्रशिक्षित करने वाले जिले के युवा मार्गदर्शक सहित महाविद्यालय के प्राध्यापक और भारी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण पर हाईकोर्ट की मुहर, 24 से ज्यादा याचिकाएं खारिज

छत्तीसगढ़ में 16,165 शिक्षकों एवं प्राचार्यों का किया गया युक्तियुक्तकरण

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और शालाओं के युक्तियुक्तकरण की नीति पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। इस नीति को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ सहित प्रदेशभर के शिक्षकों की सभी 24 से अधिक याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस बिभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा, कि शिक्षकों का स्कूलों में तर्कहीन या असमान वितरण सुधारने के लिए सरकार का यह कदम जनहित में है।

बता दें, प्रदेश के ग्रामीण और अंदरूनी क्षेत्रों के शिक्षक विहीन या एकल-शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। इसलिए 16,165 शिक्षकों एवं प्राचार्यों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य की कुल 10463 शालाओं का युक्तियुक्तकरण

किया गया है। इनमें मुख्य रूप से एक ही परिसर में संचालित हो रहे 10297 स्कूल शामिल हैं। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि यह नीति शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-25 के खिलाफ है, जिसमें स्कूलवार छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने का प्रावधान है। उनका आरोप था कि अतिशेष शिक्षकों की पहचान करते समय वरिष्ठता की अनदेखी की गई और 'लास्ट इन, फर्स्ट आउट' नियम को यांत्रिक तरीके से लागू किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद-166 के तहत राज्यपाल के नाम से विधिवत जारी नहीं किया गया।

हाईकोर्ट ने कहा- आदेश पूरी तरह से वैध

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार का 16 जुलाई 2024 का आदेश कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्यपाल के नाम से जारी किया गया था। इसलिए अदालत ने अनुच्छेद 166 के उल्लंघन की दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ऐसे कोई ठोस आंकड़े या डेटा पेश नहीं कर सके, जिससे यह साबित हो कि इस नीति से किसी स्कूल में छात्र-शिक्षक अनुपात प्रभावित हुआ है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई सरकारी नीति पूरी तरह अवैध, मनमानी या दुर्भावनापूर्ण न हो, तब तक उसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

सरकार ने 23 नए आतंकी घोषित किए:12 पाकिस्तान के रहने वाले और 11 जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को 23 लोगों को आतंकी घोषित किया है। सरकार का कहना है कि ये सभी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट व जमात उद दावा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हैं।

सरकार के मुताबिक ये लोग आतंकियों की भर्ती, भारत में घुसपैठ, आतंकी हमलों की साजिश, आतंक के लिए पैसे जुटाने, हथियार पहुंचाने और अन्य मदद करने में शामिल रहे हैं।

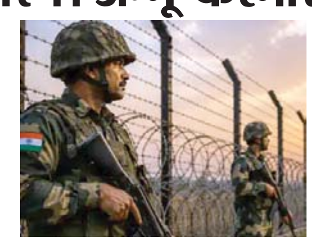

घोषित 23 आतंकियों में 11 जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी हैं, जबकि 12 पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनमें 7 पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर) और 4 पाकिस्तान में रह रहे हैं। इन 23 नामों के जुड़ने के बाद सरकार की तरफ से घोषित आतंकियों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है।

सरकार ने जिन जैश आतंकियों को लिस्ट में शामिल किया है। उनमें कुछ 2016 के नगरोटा आर्मी कैंप हमले और 2022 के सुनजवां हमले से जुड़े बताए जा रहे हैं। 29 नवंबर 2016 को जम्मू के नगरोटा आर्मी कैंप पर सेना की वर्दी पहनकर आए तीन आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में 7 जवान शहीद हुए थे।

देवकीनंद ठाकुर की भागवत कथा 8 जुलाई से

रायपुर। इंडोर स्टेडियम रायपुर में 8 जुलाई से 14 जुलाई 2026 से देवकीनंदन ठाकुर महाराज की श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम के संयोजक योगेश अग्रवाल ने सीएम विष्णुदेव साय को मुख्यअथिति के रूप आमंत्रित किया। सीएम ने कार्यक्रम में उपस्थित होने का आश्वासन दिया है।

हत्या के मामले में आरोपी किशोर को हाई कोर्ट ने दी जमानत, कहा- सजा नहीं इन्हें सुधार की जरूरत

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने बाल अपराध और न्याय के मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की एकल पीठ ने हत्या और साक्ष्य छुपाने के मामले में शामिल एक किशोर को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि किसी किशोर की जमानत केवल गंभीर अपराध के आधार पर नहीं रोकी जा सकती। कोर्ट ने सोशल स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जेल में रहने से बच्चे की पढ़ाई बाधित हो रही है, और उसे शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना आवश्यक है। मामला जांजगीर-चांपा जिले का है, जहां छह सितंबर 2025 को नौ आरोपितों ने मिलकर महेंद्र बघेल की हत्या की थी।

होर्मुज से घटा तनाव, घटकर 60 डॉलर तक पहुंच सकते हैं कच्चे तेल के दाम

नईदिल्ली। होर्मुज के आसपास तनाव कम होने से कच्चे तेल की आपूर्ति से जुड़ी चिंताएं लगभग खत्म हो गई हैं। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के निर्यात को सामान्य दरों की ओर बढ़ाने से क्रूड की कीमतों में गिरावट और गहरी हो गई है। चीन की कमजोर मांग और आपूर्ति में वृद्धि से अब बाजार में सप्लाई सरप्लस की संभावना बढ़ गई है। इससे क्रूड में और गिरावट की उम्मीद बढ़ गई है। एक रिपोर्ट में कहा, भू-राजनीतिक तनाव कम होने से ब्रेंट क्रूड ने युद्ध के दौरान हुई अपनी सारी बढ़त को गंवा दी है और इसमें 30 फीसदी की गिरावट देखी गई। हालात सामान्य होने की स्थिति में ब्रेंट क्रूड के दाम इस साल के अंत तक गिरकर 60 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकते हैं।

काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर जवान की कार्बाइन से फायरिंग, तीन लोग घायल

वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर-4बी के पास शनिवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ड्यूटी पर तैनात पीएसी के एक जवान की कार्बाइन से कथित तौर पर अचानक गोली चल गई। गोली पत्थर से टकराने के बाद उसके छर्रे और गिट्टियां आसपास मौजूद श्रद्धालुओं और लोगों की ओर उछल गईं, जिससे तीन लोग घायल हो गए।

घटना के बाद मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित कर लिया। घायलों की पहचान निक्की गुप्ता, राम बाबू और विकास यादव के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल मंडलीय चिकित्सालय, कबीरचौरा भिजवाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की हालत सामान्य बताई है। किसी भी घायल को गंभीर चोट नहीं आई है। घटना शनिवार सुबह करीब सात बजे की बताई जा रही है।

वडोदरा में व्यापारी पर फायरिंग करने वाले शूटर भिलाई से गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। गुजरात के वडोदरा में बीते 26 जून को गार्मेंट व्यापारी आशीष बकोलिया पर गोली चलाने वाले दोनों शूटर गुरजीत सिंह निवासी रिसाली? और आनंद पुरम, भिलाई निवासी विक्रम प्रताप सिंह का गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को वड़ोदरा पुलिस अपने साथ ले गए गई है। दोनों ने व्यापारी से विदेश में हुए विवाद का बदला लेने के लिए रैकी करने के बाद हत्या करने की नीयत से फायरिंग की थी।

गनीमत रही की गोली व्यापारी के हाथ में लगी थी। जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। फायरिंग करने के बाद दोनों? बदमाश भिलाई लौट आए थे। पकड़े गए शूटरों में गुरजीत सिंह भिलाई नगर थाने का लिस्टेड बदमाश है। गुजरात पुलिस को दोनों शूटरों का डेढ़ महीने पहले का एक फुटेज मिला था। इसके साथ ही होटल में एक आधार कार्ड मिला था। उसी आधार पर गुजरात पुलिस उनकी तलाश में दुर्ग आई थी। दोनों को तब पकड़ा गया जब वे एक-दूसरे से मिलने के लिए मार्केट में घूम रहे थे। आरोपी गुरजीत को दुर्ग पुलिस की टीम ने पहचान लिया। इसके बाद दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने आपरेशन चलाया। आरोपी गुरजीत को सुपेला और विक्रम को जेपी चौक से पकड़ा गया।

बड़े भाई ने छोटे पर किया कुल्हाड़ी से हमला बीच-बचाव करने आई मां भी लहूलुहान

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के बड़ेडोंगर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटपाड़ में किसी विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई के ऊपर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना को देख बीच बचाव करने आई मां भी घायल हो गई। जिन्हें उपचार के लिए फरसगांव के अस्पताल में भर्ती किया गया है।

पुलिस ने बताया कि बड़े डोंगर निवासी युवक जितेंद्र पटेल ने बीती रात को घर में खाना खा रहे अपने छोटे भाई सलीम से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद अपने छोटे भाई के ऊपर घर में रखे कुल्हाड़ी से सिर, पीठ व जांघ में हमला कर दिया। छोटे भाई ने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की। लेकिन सफल नहीं हो पाया, वहीं घर में मौजूद मां रामोतीन पटेल ने उसे बचाने की कोशिश की, इस दौरान मां भी घायल हो गई। आसपास के लोगों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए फरसगांव अस्पताल लाया गया। जहां उपचार जारी है। वही घटना के बाद से पुलिस कारणों की जांच में जुट गई है।

9, 16 व 29 जुलाई को चलेगी रथयात्रा स्पेशल, यात्रियों को मिलेगी कन्फर्म सीट

रायपुर। रथयात्रा के पावन अवसर पर यात्रियों की भीड़ और नियमित ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे भीड़भाड़ से बचने के लिए 'ट्रेन ऑन डिमांड' विशेष ट्रेनों का उपयोग करें। वर्तमान में, इन विशेष ट्रेनों में स्लीपर, एसी-3 और एसी-2 सहित सभी श्रेणियों में सैकड़ों बर्थ खाली हैं, जो यात्रियों के लिए एक सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं। यात्री अधिकृत रेलवे आरक्षण केंद्रों, आईआरसीटीसी की वेबसाइट या रेलवन एप के माध्यम से सीटों की उपलब्धता जांच कर तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। इन ट्रेनों में पुरी की यात्रा के लिए लोगों को कन्फर्म बर्थ की सुविधा मिल जाएगी।

नकटी के विस्थापितों ने सीएम हाउस घेरा, मुआवजे की मांग

- **ग्रामीणों ने अपनी जमीन वापस मांगी**

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। नकटी गांव के प्रभावित ग्रामीण मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव करने के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही।

इससे पहले गांव के लोग रायपुर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे थे। ग्रामीणों ने सीएम हाउस के सामने ही भोजन किया। इस दौरान

पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की। लोगों ने कहा कि हमारे घर तोड़ दिए गए। अब खाना भी नहीं खाने दे रहे। हालांकि, गहमागहमी के बीच लोगों ने खाना खाया। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी जमीन वापस चाहिए। तोड़े गए घरों का मुआवजा दें और लोगों पर की गई स्न्ढ्ढक्र वापस ली जाए। कलेक्टर ने 10 महिलाओं को मिलने बुलाया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांग रखी। कलेक्टर ने ऊपर तक मांग पहुंचाने की बात कही।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सुनवाई नहीं हुई तो राज्यपाल के पास जाएंगे। वहां भी सुनवाई नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ में बंद बुलाया जाएगा। 5 दिन का अल्टीमेटम देकर ग्रामीण रवाना हुए। 3 दिन पहले नकटी गांव में 80 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया था। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को मकान दिए हैं, लेकिन सभी को आवास नहीं मिला है। वहीं हाउसिंग बोर्ड का दावा है कि गांव के 77 लोगों ने 15 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया था।

बर्थडे पार्टी के दौरान गाड़ी से कुचलकर ट्रांसपोर्टर की हत्या: नशे में विवाद-मारपीट के बाद वारदात

- **कोरबा के मीरा-रिसोर्ट में जन्मदिन मनाने आए थे 20-25 दोस्त**

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के मीरा रिसोर्ट में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के बर्थडे पार्टी के दौरान नशे में विवाद और मारपीट हुई। चेकआउट के समय एक ट्रांसपोर्टर ने दूसरे ट्रांसपोर्टर की कैंपर वाहन से कुचलकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी गाड़ी लेकर फरार हो गया। मृतक की पहचान दीपका के गरुणनगर निवासी युवक उज्जवल सिंह (35) के रूप में हुई है, वो शादीशुदा था। उसके बच्चे भी हैं।

वहीं, आरोपी की पहचान तुषार ढांढा (24) के रूप में हुई है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मामला उरगा थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार देर रात दीपका क्षेत्र के ट्रांसपोर्टर विकास कुमार हुडा का जन्मदिन था। पार्टी करने के लिए 20 से 25 युवक रात को मीरा रिसोर्ट पहुंचे थे। इनमें से अधिकतर लोग कोयला ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। इस दौरान देर रात तक पार्टी हुई। रात करीब 1:30 बजे किसी मामूली बात पर युवकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। तुषार ढांढा शराब के नशे में सामान तोड़ने लगा। रिसॉर्ट में भी लोगों से झगड़ा किया। ट्रांसपोर्टर्स के बीच आपस में विवाद काफी बढ़ गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गई। इसी अफरातफरी के बीच आरोपी तुषार ढांढा ने कैंपर वाहन को उज्जवल सिंह पर चढ़ा दिया। वाहन की चपेट में आने से उज्जवल को गंभीर चोटें आईं और उसने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

संपादकीय

इथेनॉल का मोल

पहले हितधारकों की चिंताओं को दूर कीजिए

खाड़ी युद्ध के चलते उपजे ईंधन संकट ने भारत समेत पूरी दुनिया को सबक दिए हैं कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिये नये विकल्प तलाशे जाएं। भारत जैसे देश के लिये तो यह बड़ी चुनौती है क्योंकि हम पूरी तरह कच्चे तेल व गैस के लिये विदेशी संसाधनों पर ही निर्भर हैं। जिससे संकटपूर्ण स्थितियों में न केवल महंगाई बढ़ती है बल्कि हमारी दुर्लभ विदेशी मुद्रा भी दांव पर लगती है। ऐसे ही संकट से जूझने के लिये देश ने इथेनॉल के विकल्प पर गंभीरता से विचार किया। देश में पहले ही सामान्य पेट्रोल में बीस फीसदी इथेनॉल मिलाया जा रहा है। देश में विदेशी मुद्रा की बचत व आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। हाल ही में फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिये ज्यादा इथेनॉल वाले ई-85 फ्यूल उपलब्ध कराया गया। लेकिन अभी भी उपभोक्ताओं और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बीच कई मुद्दों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। दरअसल,ये वाहन ई-85 यानी 85 फीसदी इथेनॉल और 15 फीसदी पेट्रोल तथा ई-100 यानी शुद्ध इथेनॉल वाले मिश्रण पर चलने के लिये डिजाइन किये गए हैं। जबकि पेट्रोल से चलने वाली सामान्य गाड़ियां ई-20 यानी बीस फीसदी इथेनॉल और 80 फीसदी पेट्रोल के अनुकूल होती हैं। दरअसल, चुनिंदा आउटलेट्स पर ई-85 उपलब्ध कराने का निर्णय आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के मकसद से लिया गया है। यह एक हकीकत है कि आज भी देश का नब्बे फीसदी कच्चा तेल आयातित किया जा रहा है। दुनियाभर में गाहे-बगाहे पैदा होने वाले भू-राजनीतिक संकटों ने बार-बार देश के ऊर्जा इकोसिस्टम की खामियों को ही उजागर किया है। इसमें दो राय नहीं है कि फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिये इथेनॉल को मुख्य ईंधन के रूप से बढ़ावा देने का मकसद ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में बढ़ना है। वहीं दूसरी ओर इसके उपयोग से हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी ला सकते हैं।

> “ देश में विदेशी मुद्रा की बचत व आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। हाल ही में फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिये ज्यादा इथेनॉल वाले ई-85 फ्यूल उपलब्ध कराया गया। लेकिन अभी भी उपभोक्ताओं और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बीच कई मुद्दों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। दरअसल,ये वाहन ई-85 यानी 85 फीसदी इथेनॉल और 15 फीसदी पेट्रोल तथा ई-100 यानी शुद्ध इथेनॉल वाले मिश्रण पर चलने के लिये डिजाइन किये गए हैं। जबकि पेट्रोल से चलने वाली सामान्य गाड़ियां ई-20 यानी बीस फीसदी इथेनॉल और 80 फीसदी पेट्रोल के अनुकूल होती हैं। दरअसल, चुनिंदा आउटलेट्स पर ई-85 उपलब्ध कराने का निर्णय आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के मकसद से लिया गया है। यह एक हकीकत है कि आज भी देश का नब्बे फीसदी कच्चा तेल आयातित किया जा रहा है।

निश्चय ही वाहनों में इथेनॉल को बढ़ावा देना देश में आयातित कच्चे तेल के दबाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। लेकिन इस बदलाव को सिरे चढ़ाने के लिए बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे लोगों की आशंकाएं दूर हो सकें। जरूरत लोगों का भरोसा हासिल करने की है। भारत में इथेनॉल मिले तेल के उपयोग ने इससे होने वाले तमाम फायदों को साबित किया है। इससे काफी विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। साथ ही देश में इथेनॉल का सशक्त उद्योग विकसित हुआ है। यदि बाजार में इथेनॉल पर लोगों का भरोसा बढ़ता है और इसकी मांग बढ़ती है तो इससे किसानों को कमाई के नये अवसर मिल सकते हैं। इथेनॉल की ज्यादा मांग होने पर गन्ने और मक्का का बाजार विस्तार लेगा। वहीं दूसरी ओर ई-85 की कीमत पारंपरिक पेट्रोल के मुकाबले कम रखने के फैसले से, उन उपभोक्ताओं को फायदा हो सकता है, जिनके पास इसके अनुकूल गाड़ियां है। भले ही इस फ्यूल की ईंधन दक्षता कम हो, लेकिन यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को संबल देगा। बहरहाल, इस उम्मीद के साथ ही, हमें हकीकत का भी ध्यान रखना है। दरअसल, ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने इंजन की क्षमता, जंग लगने, ईंधन सिस्टम पर प्रभाव और इसकी दीर्घकालिक क्षमता को लेकर चिंताएं जतायी हैं। निस्संदेह, इन मुद्दों को सीधे खारिज करने के बजाय इन पर गंभीर रूप से मंथन करना चाहिए। अगर इन मुद्दों का निराकरण नहीं होता है तो भ्रम व संशय की स्थिति बनी रहेगी। जिसे अविलंब दूर करने की भी जरूरत है। इस वैकल्पिक ईंधन की सहज उपलब्धता के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर व गाड़ियों को इसके अनुरूप बनाना, वैकल्पिक ईंधन की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण तथा इससे जुड़े तकनीकी प्रशिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि बॉयोफ्यूल इतनी जल्दी फॉसिल फ्यूल का विकल्प नहीं बन सकता। इस बाबत पर्याप्त तैयारी, पारदर्शिता और सभी हितधारकों का सहयोग लेना जरूरी है। इस मामले में जल्दबाजी करने से बचा जाना चाहिए। यदि हम सजगता व सतर्कता से आगे बढ़ते हैं तो ई-85 एक सफल मॉडल बन सकता है। अन्यथा हम एक अच्छा मौका चूक सकते हैं।

नारी शक्तिः वादों से लेकर कर दिखाने तक, ब्रिक्स में भारत का योगदान

अन्नपूर्णा देवी

भारत ने 1 जनवरी 2026 को लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण की थीम के तहत ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। महिलाओं से जुड़े मामलों में हमारा योगदान बेहद खास रहा है। हम सिर्फ कोई नारा या तारीफ के लिए सफल कहानियों का संग्रह पेश नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसा कामकाजी ढांचा लेकर आए हैं, जो करोड़ों महिलाओं तक पहुँचा है। यह ढांचा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां से शुरू होकर जहाँ भी जाता है, वहाँ आगे और विकसित होने के लिए तैयार रहता है।

यही भारत की खास बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से भारत ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर अपनाया है और इस काम को इतने बड़े पैमाने पर किया है, जिसकी बराबरी बेहद कम देश कर सकते हैं। 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान, भारत ने वैश्विक सोच को महिलाओं के विकास से बदलकर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर मोड़ने में मदद की। यह महज़ शब्दों का बदलाव नहीं था, बल्कि सोच का भी बदलाव था। महिलाओं को सिर्फ़ लाभार्थी के तौर पर देखने के बजाय, उन्हें नेतृत्वकारी भूमिका में देखना। कोच्चि में हम इसी बदलाव से जुड़ा सवाल उठा रहे हैं: एक बार वादा करने के बाद, उसे बड़े पैमाने पर, आख़िरी गाँव की आख़िरी महिला तक कैसे पहुँचाया जाए? भारत ने पिछले दस सालों में सिर्फ़ सैद्धांतिक तौर पर नहीं, बल्कि असल में इस सवाल का जवाब दिया है।

भारत के लिए यह सोच नई नहीं, बल्कि बहुत पुरानी है। विकास की भाषा के आने से काफी पहले ही, हमारी संस्कृति ने नारी को शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का स्रोत माना था। ये तीनों ही वे आधार हैं, जिन पर कोई भी समाज तरक्की करता है और उन्हें देवी दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता रहा है। दैवीय शक्ति को ही 'शक्ति' कहा जाता है और संस्कृत के एक प्रसिद्ध श्लोक के अनुसार, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ देवता भी प्रसन्न होते हैं। यह सम्मान सिर्फ़ दिखावे के लिए नहीं था: लोपामुद्रा और घोषा जैसी महिला ऋषियों ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की और गार्गी और मैत्रेयी जैसी दार्शनिकों ने उपनिषदों के प्रसिद्ध वाद विवादों में अपनी बात मज़बूती से रखी। इसलिए, भारत के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास, किसी और से लिया हुआ विचार नहीं है, बल्कि एक प्राचीन विचार का ही आधुनिक रूप है। शुरुआत फैसला लेने की प्रक्रिया से करते हैं। भारत की पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए प्रतिनिधियों में से लगभग आधी महिलाएँ हैं, जो दुनिया में चुनी हुई महिला नेताओं के सबसे बड़े समूहों में से एक है। इसके अलावा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का अंत सिर्फ प्रतिनिधित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहां से इसकी शुरुआत होती है। ऐसा मॉडल, जो महिलाओं को सेवाएँ तो देता है, लेकिन उन सेवाओं को तय करने वाले फैसलों में उन्हें शामिल नहीं करता, वह असल में महिलाओं के नेतृत्व वाला मॉडल नहीं है।

भारत में सेवा पहुँचाने का ढाँचा तीन हिस्सों पर टिका है, जो एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। पहला हिस्सा है पहुँच: डिजिटल जन अवसंरचना, फायदों को सीधे महिलाओं के हाथों तक पहुँचाती है। आधार से जुड़े ट्रांसफर उन बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर रहे हैं, जो पहले मदद पहुँचने से पहले ही उसे दूसरी तरफ मोड़ देते थे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इस पहुँच का व्यावहारिक उदाहरण है। 4.26 करोड़ से ज़्यादा माताओं को मातृत्व लाभ के तौर पर 20,060 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि सीधे उनके आधार से जुड़े खातों के ज़रिए मिली है। दूसरा हिस्सा है संस्थाएँ: डीएवाई-एनआरएलएम के तहत, 10.05 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं को 90.90 लाख से ज़्यादा स्वयं-सहायता समूहों में संगठित किया गया है, जो दुनिया में महिलाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक संस्थाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तीसरा हिस्सा है गतिशीलता—यानी मूल्य श्रृंखला में हमेशा सबसे नीचे बने रहने के बजाय ऊपर की ओर बढ़ने का एक सोच-समझकर चुना गया रास्ता। भारत अब 65,949 एसएचजी महिलाओं को बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट यानी बीसी सखी के तौर पर तैनात कर रहा है, जो दूर-दराज़ के इलाकों में जमा, क्रेडिट, धनराशि भेजने और पेंशन सेवाएँ पहुँचाती हैं। जो महिला कभी किसी लाभ के लिए कतार में लगती थी, अब वही महिला उस लाभ को दूसरों तक पहुँचाती है।

कुल मिलाकर ये सब मिलकर भागीदारी को आमदनी और मालिकाना हक में बदलते हैं। लखपति दीदी पहल के तहत, जून 2025 तक 1.48 करोड़ स्वयं सहायता समूह महिलाओं की सालाना कमाई कम से कम 1 लाख रुपए तक पहुँच गई थी और जनवरी 2026 में शुरू किए गए उद्यमिता पर केंद्रित एक राष्ट्रीय अभियान का मकसद 50,000 सामुदायिक संसाधन व्यक्ति के ज़रिए 50 लाख अतिरिक्त महिलाओं को प्रशिक्षण देना है। तरक्की का यही रास्ता औपचारिक कारोबार में भी दिखता है: पीएमएमवाई के तहत दिए गए ऋण में से 69 प्रतिशत और 'स्टैंड-अप इंडिया' के लाभार्थियों में से 84 प्रतिशत महिलाएँ हैं। डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त 2.12 लाख स्टार्टअप्स में से 1.02 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक या हिस्सेदार है और इनमें से कई स्टार्टअप बड़े शहरों के बजाय छोटे शहरों में हैं। हम ब्रिक्स को ये ब्रांड नाम नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानी पेश करते हैं: पहले पहुँच, फिर संस्थाएँ और फिर लाभार्थी से उद्यमी बनने का एक व्यवस्थित मार्ग।

आँकड़े भी इस बदलाव को दिखाते हैं। भारत में महिलाओं की कामकाजी आबादी में भागीदारी 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गई है और इसी दौरान महिलाओं में बेरोज़गारी दर 5.6 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई है। अब पहले से कहीं ज़्यादा महिलाएँ कार्यबल का हिस्सा हैं, इसलिए हमारा फोकस अब अगले चरण पर है, उनके काम की गुणवत्ता और आमदनी को और बेहतर बनाना।

इस साल महिलाओं से जुड़े कामों के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्र तय किए गए हैं और इनमें से एक सीधे हमारे अनुभव से जुड़ा है: जलवायु कार्यवाही, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका। इस बारे में साक्ष्य भी साफ नतीजे बयां करते हैं: जब फैसले लेने की प्रक्रिया में महिलाएं शामिल होती हैं, तो पोषण बेहतर मिलता है और समुदाय चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। झारखंड में महिला किसानों को ऐसी बीजों की किस्मों की जानकारी है, जो सूखे के दौरान भी बची रहती हैं।

राजस्थान में महिला पशुपालकों को उन रास्तों की भी जानकारी है, जिनसे सूखे के समय मवेशियों को सुरक्षित ले जाया जा सकता है। भारत का काम ऐसे संस्थान बनाना रहा है, जो इस जानकारी और अनुभव का इस्तेमाल करें, न कि इसे नज़रअंदाज़ करें। मिशन पोषण 2.0 आंगनवाड़ी नेटवर्क के ज़रिए चलाया जाता है, जिसमें महिलाएं काम करती हैं और वे ही लोगों तक सेवा पहुंचाने की भरोसेमंद कड़ी होती हैं। जलवायु के अनुसार ढलने का काम भी इसी तरह होता है, चाहे वह लद्दाख में महिलाओं द्वारा बनाए गए ऊंचे इलाकों में पानी जमा करने के ढांचे हों या ओडिशा के तट पर वनस्पति के घने इलाकों को बचाने वाली समितियां। महिलाएं अब सिर्फ़ अनुकूलन की तकनीक का इस्तेमाल करने वाली नहीं रह गई हैं, बल्कि वे खुद इसे आगे बढ़ा भी रही हैं: नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को खेती में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह ज़्यादा कौशल और ज़्यादा आमदनी वाले काम की ओर एक सोच-समझकर उठाया गया कदम है।

एक खास बात जो पूरी तरह से भारत की वास्तविक विशेषता बन गई है। एक ज़िला एक उत्पाद पहल के तहत अब 761 ज़िलों में 1,102 उत्पाद शामिल हैं। महिला समूह हथकरघा, जीआई टैग वाले शिल्प और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों जैसे स्थानीय विशेष उत्पादों को ब्रांडेड और तेज़ी से निर्यात होने वाले उत्पादों में बदल रहे हैं। सरकार भी इन उत्पादों के लिए बाज़ार तक पहुँचने का रास्ता बना रही है: अवसर योजना के तहत हवाई अड्डों पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिटेल जगह और 'वोकल फॉर लोकल' के तहत महिला-संचालित उद्यमों के लिए जेम पर एक खास स्थान। असल मायनों में यह टिकाऊ व्यवस्था है, जिसके तहत स्थानीय सामग्री, स्थानीय कौशल और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला, जो समुदाय के भीतर ही अपना मूल्य बनाए रखती हैं और ये विकास का ऐसा रूप भी है, जिसके लिए किसी महिला को बाज़ार तक पहुँचने के लिए अपना ज़िला छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास सरकार द्वारा की गई महज़ कोई घोषणा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसे एक-एक हिस्से को जोड़कर तब तक बनाया और संचालित किया जाता है, जब तक कि यह उस आखिरी महिला तक न पहुँच जाए, जिसके लिए इसे बनाया गया था। जुलाई में कोच्चि में होने वाली मंत्रियों की बैठक में, भारत इस मॉडल को एक योगदान के तौर पर पेश करेगा, न कि किसी ऐसे उपाय के तौर पर, जिसे दूसरों को भी अपनाना ही हो। इसका मकसद यह है कि दूसरे इससे सीख सकें और इसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकें। यही व्यवस्था और इसके सफल होने के सबूत, भारत ब्रिक्स के सामने रख रहा है। यह आदान-प्रदान दोनों तरफ से होता है: भारत कोच्चि में अपने ब्रिक्स सहयोगियों के बेहतरीन तौर-तरीकों से सीखने और अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार है।

लेखिका भारत सरकार में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं

समुद्र से हो सकता है पेयजल मंथन

दीपक कुमार शर्मा

यदि भारत में उपलब्ध जल का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए और समुद्री जल शोधन जैसी आधुनिक तकनीकों को साथ जोड़ा जाए, तो आने वाले दशकों में जल संकट की गंभीरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

देश के अनेक शहरों और गांवों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। नदियां प्रदूषित हो रही हैं, वर्षा का स्वरूप अनिश्चित होता जा रहा है और जलवायु परिवर्तन ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण पानी की मांग लगातार बढ़ रही है।

तीन ओर से समुद्र से घिरे भारत के सामने जल का असीमित भंडार मौजूद है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97 प्रतिशत भाग समुद्रों में खारे पानी के रूप में है, जबकि केवल लगभग 2.5 प्रतिशत जल मीठा है। इसमें भी अधिकांश जल हिमनदों और बर्फ की चादरों में बंद है तथा मानव उपयोग के लिए सीधे उपलब्ध मीठा जल एक प्रतिशत से भी कम है। ऐसे में समुद्री जल को शुद्ध कर उपयोग योग्य बनाना भविष्य की आवश्यकता बनता जा रहा है।

आज आधुनिक विज्ञान की सहायता से समुद्री जल से नमक और अन्य अशुद्धियां हटाकर उसे पेयजल में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे समुद्री जल शोधन कहा जाता है। विश्व के अनेक देशों ने इसे अपनी जल सुरक्षा की आधारशिला बना लिया है। भारत के लिए भी अब इस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ने का समय आ गया है।

सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे देशों में प्राकृतिक मीठे जल के स्रोत अत्यंत सीमित हैं। वहां वर्षा नगण्य होती है और अधिकांश भूभाग रेगिस्तान है। इसके बावजूद वहां नागरिकों को चौबीसों घंटे सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। इसका मुख्य कारण समुद्री जल शोधन संयंत्र हैं। भारत की स्थिति खाड़ी देशों से अलग अवश्य है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। विश्व की लगभग 18 प्रतिशत आबादी भारत में रहती है, जबकि मीठे जल संसाधनों में उसकी हिस्सेदारी केवल लगभग 4 प्रतिशत है। देश में उपलब्ध मीठे जल का लगभग 80 प्रतिशत उपयोग कृषि क्षेत्र करता है। दूसरी ओर, उद्योगों और शहरों की बढ़ती आवश्यकताओं ने जल संकट को और गहरा कर दिया है।

सबसे बड़ी चिंता भूजल का लगातार दोहन है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु सहित अनेक राज्यों में भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। कई क्षेत्रों में हर वर्ष लगभग एक मीटर तक जल स्तर गिरने की रिपोर्ट सामने आती रही है। ऐसे समय में समुद्री जल शोधन भारत के लिए एक रणनीतिक विकल्प बन सकता है। देश के पास लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर समुद्री जल शोधन परियोजनाएं विकसित की जा सकती हैं। इससे तटीय शहरों की पेयजल आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पूरा किया जा सकता है और भूजल पर निर्भरता कम होगी।

चेन्नई इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आज यह अपने पेयजल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्री जल शोधन संयंत्रों से प्राप्त करता है। गुजरात के दहेज, जामनगर और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी इस तकनीक का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। हालांकि, यह भी सत्य है कि समुद्री जल शोधन कोई जादुई समाधान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती लागत है। संयंत्रों की स्थापना, संचालन और रखरखाव पर भारी निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, बड़ी मात्रा में ऊर्जा की भी जरूरत पड़ती है। यदि ऊर्जा का स्रोत जीवाश्म ईंधन हो, तो लागत बढ़ने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ता है। आज भारत विश्व के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में शामिल है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विशाल सौर एवं पवन ऊर्जा क्षमता उपलब्ध है। यदि समुद्री जल शोधन संयंत्रों को नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़ा जाए, तो उनकी परिचालन लागत और कार्बन उत्सर्जन दोनों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। एक अन्य चुनौती पर्यावरण संरक्षण की है। समुद्री जल से नमक अलग करने के बाद अत्यधिक खारा अवशेष बचता है। यदि इसे वैज्ञानिक उपचार के बिना समुद्र में छोड़ दिया जाए, तो समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक नई परियोजना के साथ कठोर पर्यावरणीय मानकों का पालन और आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। भारत को इस क्षेत्र में चरणबद्ध रणनीति अपनानी चाहिए।

दुनिया की छत से इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की तैयारी

पुष्परंजन

चीन का मानना है कि 'दुनिया की छत' तिब्बत से लॉन्च किए गए रॉकेट भारत के भीतर तक जा सकते हैं। चीनी एक्सपर्ट्स ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट से लॉन्च किया गया रॉकेट पारम्परिक रॉकेट से अधिक स्थिर और अचूक होगा, साथ ही यह अपने भार को गति देने वाली मिसाइल से बहुत सस्ता भी होगा।

जो तिब्बत 'दुनिया की छत' के नाम से मशहूर था, अब चीन उसे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मार्ग वाले रॉकेट लॉन्चिंग अधिकेंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। पेइचिंग इंस्टिच्यूट ऑफ़ स्पेस साइंस के अंतरिक्ष विज्ञानी यू थांग ने पिछले हफ़्ते कहा, 'चीन की स्पेस इंडस्ट्री के कुछ बहुत ही साहसी और होनहार युवाओं ने दो दशक से भी ज़्यादा समय पहले शिंगहाई-तिब्बत पठार के ऊंचाई वाले और कम हवा वाले इलाकों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च ऑर्बिट बनाने का आइडिया दिया था। अब वो साकार हो रहा है।'

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रॉकेट लॉन्च टेक्नोलॉजी, एक क्रांतिकारी अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली है, जो पारंपरिक केमिकल, ईंधन के बजाय शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों (मैग्नेटिक फील्ड) का उपयोग करके रॉकेट या पेलोड को अंतरिक्ष में लॉन्च करती है। यह तकनीक लक्ष्य तक पहुंचने में सटीक है, और अंतरिक्ष यात्रा की लागत को काफी हद तक कम करने की क्षमता रखती है।

इस प्रणाली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैक (विद्युत चुम्बकीय पटरियों) का उपयोग किया जाता है, जो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा (कायनेटिक एनर्जी) में बदलती हैं। एक बार आवश्यक गति प्राप्त करने के बाद, पेलोड या छोटा रॉकेट वातावरण में ऊपर की ओर छूट जाता है, और अंतरिक्ष के लिए अपनी यात्रा जारी रखता है। इससे भारी मात्रा में ईंधन की बचत होती है। इसे ध्यान में रखें कि पारंपरिक रॉकेटों के कुल वजन का 80-90 प्रतिशत हिस्सा केवल ईंधन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर इस ईंधन के भार को खत्म कर देते हैं, जिससे रॉकेट बहुत अधिक पेलोड (उपग्रह या उपकरण) ले जा सकते हैं। यह तकनीक अंतरिक्ष यान को पारंपरिक केमिकल इंजनों की तुलना में कहीं अधिक गति देती है। इससे मंगल ग्रह की यात्रा का समय 8-9 महीने से घटकर केवल 30-60 दिन होने का दावा किया जा रहा है। यह 300 किलोवाट तक की शक्ति पर काम करता है, और हाइड्रोजन के आवेशित कणों (प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन) को 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की आश्चर्यजनक गति प्रदान करता है।

भारत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक (विद्युत-चुंबकीय) रॉकेट लॉन्च तकनीक अभी भी शुरुआती अनुसंधान और विकास के चरण में है। भारत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम (ईएमएएलएस) चीन से काफी पीछे है। चीन फुज़ियान (टाइप 003) विमान वाहक पर अपने विद्युत चुम्बकीय कैटापुल्ट को सफलतापूर्वक चालू कर चुका है, अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला वह दुनिया का दूसरा देश है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ग्राउंड फोर्स रिसर्च इंस्टिट्यूट में तैनात प्रोफेसर हान ने इसे दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट बताया,

और कहा कि यह पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक बड़ी सफलताओं के साथ लगातार चल रहा है। हान ने '4,000 मीटर (13,123 फुट) से ज़्यादा ऊंचे पठार से सीधे डेटा इकट्ठा किया है। उन्होंने इस पर अनुसंधान किया है कि रॉकेट को ज़्यादा ऊंचाई वाले माहौल के लिए कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए, जहां सर्दियों में तापमान बहुत कम होता है, जिससे हवा का दबाव कम होता है। यह समुद्र तल के प्रेशर का लगभग आधा हो सकता है। इसका मतलब है उड़ान के दौरान हवा का घर्षण कम होता है, और शायद रेंज भी ज़्यादा होती है, खासकर तिब्बत जैसे दुनिया की छत पर रॉकेट को और भी ज़्यादा पावरफुल हथियार बना देगा।'

ज़ियांग चीन के पूर्वी सिचुआन प्रांत का शहर है। 2026 की शुरुआत में ज़ियांग में हाई-टेम्परेचर सुपरकंडक्टिंग नेविगेशन सिस्टम के सफल परीक्षण ने इस टेक्नोलॉजी को हकीकत के करीब ला दिया है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व 'ज़ियांग कमर्शियल एयरोस्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टिट्यूट' के शोधार्थी कर रहे हैं, जो चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की एक शाखा है। तकनीकी सफलताओं के बावजूद, अभी भी इंजीनियरिंग से जुड़ी बड़ी चुनौतियां बाकी हैं। ज़ियांग फ़ैसिलिटी चीन के पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म को सक्रिय रूप से चला रही है, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2028 तक 'इसरो' की तरह व्यावसायिक लांच वाले पैटर्न पर लाना है। अब सवाल है, क्या चीन इस तकनीक का सैन्य इस्तेमाल भी करने के प्रयास में है? चीन विद्युत-चुंबकीय तकनीक का इस्तेमाल मिसाइल और रॉकेट लॉन्चिंग के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में आक्रामक रूप से कर रहा है। पारंपरिक रासायनिक ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए, चीन इस तकनीक को जीरो-स्टेज बूस्टर के रूप में विकसित कर रहा है।

चीन की ज़ियांग कमर्शियल एयरोस्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टिट्यूट एक ऐसे सुपरकंडक्टिंग मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम पर काम कर रही है, जो रॉकेट को जमीन से ही ट्रैक पर बिजली के जरिए सुपरसोनिक गति देने में सक्षम है। मिसाइल तकनीक के साथ चीन उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव (एचपीएम) और ईएमपी हथियारों का निर्माण कर रहा है। चीन ने अंतरिक्ष में मौजूद दुश्मन के सैटेलाइट्स या संचार प्रणालियों को बिना किसी विस्फोट के जाम या नष्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक का उपयोग कर रहा है। चीन, अपने फूचियान जैसे अत्याधुनिक विमान वाहक पोतों पर युद्धक विमानों को लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है। चीनी मीडिया का दावा है कि यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सरफेस-टू-सरफेस रॉकेट होगा। तिब्बत में इनका टेस्ट क्यों किया जा रहा है? इस बारे में चीन का मानना है कि 'दुनिया की छत' तिब्बत से लॉन्च किए गए रॉकेट भारत के भीतर तक जा सकते हैं। चीनी एक्सपर्ट्स ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट से लॉन्च किया गया रॉकेट पारम्परिक रॉकेट से अधिक स्थिर और अचूक होगा, साथ ही यह अपने भार को गति देने (प्रोपल्शन सिस्टम) वाली मिसाइल से बहुत सस्ता भी होगा। मगर सवाल है, क्या हमारी सीमाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संचालित रॉकेट प्रणाली से सुरक्षित रहेंगी? चीन के साथ भारत की 4,056 किलोमीटर लंबी सीमा को दशकों से नजरअंदाज किया गया है। समय-समय पर भारतीय अधिकारी इसे अभेद बनाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पिछली सरकार के प्रयासों की आलोचना करते थे, लेकिन पिछले दशकों में भी कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है।

दिक्कत यह है कि सरकार देश में रणनीतिक ढांचे के निर्माण के लिए जिम्मेदार सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) पर ही निर्भर है। बीआरओ की कार्यशैली में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं दिखाई देता है। चीन ने जिस रफ्तार में अपने इलाके में ऑल वेदर मेटालिक रोड और अधोसंरचना खड़े किये, बीआरओ उसके मुक़ाबिल कछुआ गति से आगे बढ़ता रहा है। बीआरओ में कुशल कर्मियों की कमी एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में पूरे बॉर्डर लाइन पर चीनी तैयारी के मुक़ाबले हम कब गंभीर होंगे? इस सवाल पर विमर्श ज़रूरी है।

लेखक जियो-पॉलिटिकल मामलों के पत्रकार हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई–दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

संविदा कार्यादेश अपलोड करने हेतु स्वचालित प्रणाली विकसित की

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) ने वैधानिक अनुपालन को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पोर्टल पर संविदा कार्यादेश (कांट्रेक्टचुअल वर्क आर्डरस) अपलोड करने के लिए एक स्वचालित (ऑटोमेटेड) प्रणाली विकसित कर सफलतापूर्वक लागू की है। यह प्रणाली ईपीएफओ के निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप विकसित की गई है, जिससे वैधानिक प्रक्रियाओं का समयबद्ध एवं त्रुटिरहित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। ईपीएफओ के दिशा–निर्देशों के अनुसार भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा जारी सभी संविदा कार्यादेशों को ईपीएफओ पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया को सरल, त्वरित एवं पूर्णतः स्वचालित बनाने के उद्देश्य से वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा बॉट आधारित ऑटोमेशन प्रणाली विकसित की गई है, जो संयंत्र की आंतरिक सूचना प्रणाली एवं ईपीएफओ पोर्टल के बीच निर्बाध समन्वय स्थापित कर कार्य करती है। इस स्वचालित प्रणाली का शुभारंभ कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) प्रवीण निगम एवं कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार ने इस्पात भवन स्थित कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) के सभागार में किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक राजीव महेंद्रु सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

चार वार्डों को मिली विकास कार्यों की सौगात

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार विकास कार्यों को गति दी जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को महापौर अलका बाघमार ने वार्ड क्रमांक 47, 04, 09 एवं 54 में सड़क, नाली एवं पुलिया निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत भूमिपूजन कर निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। वार्ड क्रमांक 47 सिविल लाइन उत्तर में मनीष राजपूत के घर से गीता बाघ के घर तक आरसीसी नाली एवं पुलिया निर्माण, गिरधारी किराना स्टोर से शिखर प्रसाद के घर तक सीसी रोड निर्माण तथा दीपक मोटवानी के घर से जगदीश पाल के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 04 गया नगर में परमेश्वरी स्कूल के सामने एवं अन्य स्थानों पर आरसीसी नाली एवं पुलिया निर्माण, उत्तम साहू के घर के पास पुरुषोत्तम किराना के पीछे सड़क निर्माण तथा शिव नगर में पृथ्वीराज हाउस के समीप गली क्रमांक 9 एवं 10 तक आरसीसी नाली निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया वार्ड क्रमांक 09 में मनोहर यादव के घर से राहुल के घर तक सीसी रोड निर्माण तथा नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। वहीं वार्ड क्रमांक 54 में भी नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन संपन्न हुआ। भूमिपूजन के अवसर पर महापौर अलका बाघमार ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने तथा निर्धारित समय–सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

2026 के प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु मध्यस्थ अधिवक्ताओं की बैठक संपन्न

दुर्ग। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय को अधिक सुलभ, सरल एवं सहभागी बनाने के उद्देश्य से संचालित समाधान समारोह–2026 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों के सफल एवं समयबद्ध निराकरण हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के. विनोद कुजूर की अध्यक्षता में मध्यस्थ (Mediator) अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में समाधान समारोह के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों के अधिकाधिक सौहार्दपूर्ण एवं सहमति आधारित निराकरण के लिए आवश्यक कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण में पक्षकारों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए तथा जिन प्रकरणों में आवश्यक हो, उनमें पुनः समन जारी कर समय पर तामील कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि समाधान समारोह को सफल बनाने के लिए सभी अधिवक्ताओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाए तथा प्रत्येक प्रकरण में समझौते की संभावनाओं का गंभीरतापूर्वक प्रयास किया जाए।

बैठक के दौरान प्रकरणों के निराकरण में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों, पक्षकारों की उपस्थिति, समन तामील, मध्यस्थता की प्रक्रिया तथा अन्य प्रशासनिक एवं व्यवहारिक विषयों पर विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए गए।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (चेक अनादरण) के प्रकरणों की विशेष लोक अदालत की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर सफलतापूर्वक निराकरण कराने हेतु सक्रिय एवं समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि समाधान समारोह–2026 एवं विशेष लोक अदालत का उद्देश्य केवल लंबित प्रकरणों का निराकरण करना ही नहीं, बल्कि पक्षकारों को त्वरित, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों, मध्यस्थों एवं अधिवक्ताओं से इस जनहितकारी पहल को सफल बनाने में पूर्ण समर्पण एवं सक्रिय सहभागिता निभाने का आग्रह किया।

बैठक में स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत, दुर्ग की अध्यक्ष सुषमा लकड़ा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर एवं मध्यस्थ अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

पीएम राहत योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए संभाग स्तर पर दिया गया प्रशिक्षण

योजना के तहत सड़क हादसे में घायलों को मिलेगा डेढ़ लाख तक का कैशलेस इलाज

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित और प्रभावी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में पीएम राहत योजना एवं ई–डार प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को समय पर और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 'पीएम राहत योजना' लागू की गई है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख रूपए तक का निःशुल्क एवं कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा।

उक्त प्रशिक्षण का संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के तकनीकी निदेशक अमित देवांगन, स्टेट मैनेजर सारांश ने किया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि इसका उद्देश्य दुर्घटना के बाद उपचार में होने वाली देरी को रोकना तथा पीड़ितों की जान बचाना है। योजना को 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे दुर्घटना की सूचना मिलते ही निकटतम अस्पताल की पहचान करने अथवा एम्बुलेंस उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। इसके माध्यम से पीड़ितों को शीघ्र चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जा सकेगी।

घायल मरीजों को समय पर मिल सकेगा इलाज

योजना के अंतर्गत सामान्य मामलों में दुर्घटना के बाद प्रारंभिक 24 घंटे तथा गंभीर एवं जीवन रक्षक उपचार की आवश्यता वाले मामलों में 48 घंटे तक तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे गंभीर रूप से घायल मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा। पीएम राहत योजना का संचालन पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। इस अवसर पर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटना के बाद पहला घंटा जिसे गोल्डन आवर' कहा जाता है, घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है।

समय पर इलाज मिलने से घटेगी मौतों की संख्या

समय पर सही इलाज मिलने से सड़क हादसों में होने वाली अधिकांश मौतों को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती आबादी के साथ यातायात का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान और आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राहत योजना संचालित की जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी और परिवहन अधिकारी को अपनी–अपनी जिम्मेदारियों और भूमिका की विस्तृत जानकारी होना आवश्यक है, ताकि दुर्घटना की स्थिति में समन्वित एवं त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

सूचीबद्ध चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार उपलब्ध

प्रशिक्षण में प्रधानमंत्री राहत कैशलेस उपचार योजना के उद्देश्य और प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इसके तहत पीड़ितों को सूचीबद्ध चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है। योजना के डिजिटल क्रियान्वयन में डेटा प्रबंधन, सत्यापन और उपचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान आईआरडी एवं ई–डार प्रणाली, डेटा एंट्री वर्कफ्लो और दुर्घटना डेटा प्रबंधन से संबंधित तकनीकी और कार्यात्मक पहलुओं पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।

निगम ने 40 महिला स्व-सहायता समूहों को दिया 3 माह का मानदेय और सम्मान

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई ने शुक्रवार को अमृत मित्र 2.0 वूमन फॉर ट्री योजना से जुड़ी 40 महिला स्व–सहायता समूहों को तीन माह का लंबित मानदेय ऑनलाइन जारी कर सम्मानित किया। निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक रिकेश सेन, निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, उपायुक्त दिनेश कोसरिया, अधीक्षण अभियंता अजीत तिग्गा उपस्थित रहे।

अमृत मित्र 2.0 वूमन फॉर ट्री योजना के तहत कार्यरत 40 महिला स्व–सहायता समूहों के 125 महिलाओं के तीन माह से लंबित मानदेय का ऑनलाइन भुगतान उनके खातों में किया गया। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विधायक रिकेश सेन ने महिलाओं के इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए सराहना करते हुये लोकंगण आने का निमंत्रण दिये हैं उनका वूमेन फॉर ट्री योजना अंतर्गत रोपित पौधों के प्रति विशेष लगाव दिखा। नेताप्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने महिलाओं से आग्रह किये हैं कि इस कार्य को हमेशा जारी रखा जाए जिससे शहर के हरियाली में और वृद्धि हो। निगम आयुक्त शासन के महत्वपूर्ण योजना से शहर हरियाली में वृद्धि के लिए स्व सहायता समूह के दीदियों को बधाई दिये और आगामी समय में दिक्कत ना हो, उसके लिए आश्वस्त किये।

महिलाओं के सम्मान के उपरांत निगम परिसर में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं महिला समूहों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और अधिक से अधिक वृक्षारोपण का संकल्प लिया। इस अवसर पर लेखाधिकारी चंद्रभूषण साहू, उद्यान सह जनसंपर्क अधिकारी तिलेश्वर साहू, सहायक अभियंता फ्तेलाल साहू, उप अभियंता श्वेता महेश्वर, पार्षद गिरजा बंछोर, सरिता देवी सहित महिला स्व सहायता समूह की सदस्य उपस्थित रहीं।

भिलाई निगम ने अवैध अतिक्रमण से प्रभावित 7 परिवारों को दिया अस्थायी आवास

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ मानवीय संवेदनाओं का भी परिचय दिया है। शुक्रवार को निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रभावित 7 परिवारों को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से अस्थायी आवास आबंटित किए गए, ताकि स्थायी आवास बनने तक उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश के पालन में निगम ने अवैध कब्जों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की थी। जिस भूमि से अतिक्रमण हटाया गया, उसी स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। निर्माण कार्य पूर्ण होने तक प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी निभाते हुए निगम ने उन्हें अस्थायी आवास उपलब्ध कराया। कार्यक्रम में विधायक रिकेश सेन ने कहा कि सरकार और निगम का उद्देश्य केवल अवैध कब्जे हटाना नहीं, बल्कि पात्र जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द ही इन परिवारों को स्थायी आवास मिलेंगे।

निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे, इसके लिए लॉटरी प्रणाली से अस्थायी आवास आबंटित किए गए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य तेजी से पूरा कराया जाएगा ताकि परिवार जल्द अपने स्थायी घरों में प्रवेश कर सकें। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, उपायुक्त दिनेश कोसरिया, अधीक्षण अभियंता अजीत तिग्गा, जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता, उप अभियंता दीपक देवांगन, पार्षद गिरजा बंछोर, सरिता देवी तथा आवास प्रभारी विद्याधर देवांगन उपस्थित रहे।

नेहरू नगर में अवैध प्रीकास्ट बाउंड्रीवाल पर चला बुलडोजर, 4 अवैध कब्जे हटाए

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई ने अवैध अतिक्रमण और कब्जों के खिलाफ एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए नेहरू नगर क्षेत्र में चार अलग–अलग अवैध प्रीकास्ट बाउंड्रीवाल को ध्वस्त कर दिया। निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने जेसीबी की मदद से कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया।

नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार सभी जोन क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण, कब्जे और बिना अनुमति किए गए निर्माणों के खिलाफलगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जोन–1 क्षेत्र के नेहरू नगर स्थित हाईटेक हॉस्पिटल के समीप मॉडल टाउन में अवैध रूप से प्रीकास्ट बाउंड्रीवाल बनाकर दुकानें संचालित किए जाने की शिकायत निगम को मिली थी।

वार्ड प्रभारी की जांच रिपोर्ट में शिकायत सही पाए जाने के बाद निगम प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया। राजस्व विभाग, बेदखली दस्ता और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन से चारों अवैध प्रीकास्ट बाउंड्रीवाल को हटाकर कब्जा मुक्त कराया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, बिना अनुमति निर्माण और अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

किसानों के हितों की रक्षा के लिए मैदानी स्तर पर कृषि विभाग

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। खरीफ सीजन 2026 को ध्यान में रखते हुए किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय निरीक्षण दल एवं जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा मेसर्स अथर्वा एग्रो कैमिकल प्राईवेट लिमिटेड, रवेलीडीह विकासखंड दुर्ग का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर में कीटनाशकों के विनिर्माण संबंधि दस्तावेजों के अवलोकन से पाया गया कि अधिकांश कीटनाशकों का टेक्नीकल ग्रेड क्रय किया गया है परंतु कुछ उत्पाद का सीधे फार्मूलेटेड कीटनाशक विभिन्न कंपनियों से भारी मात्रा में क्रय कर अपनी पैकेंजिग में पैक कर विक्रय किया गया, इस हेतु स्पष्ट दस्तावेज निरीक्षण दल को अवलोकन नही कराये जाने के कारण कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत कीटनाशक दवाईयों ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5 प्रतिशत एल 780 लीटर, इमाजेथापायर 1200 लीटर, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 5 प्रतिशत एसपी 1065 कि.ग्रा, पेंडिमेथालिन 38.7 प्रतिशत सीएस 84 लीटर, ग्लाइफोसेट आइपीएस साल्ट 41 प्रतिशत एसएल 3310 लीटर, का विक्रय प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विभिन्न ग्रेड के उर्वरक

आयात एवं बायोस्टीमुलेन्ट के विनिर्माण अनुज्ञापन के संबंध में पूछे जाने पर कंपनी द्वारा विभिन्न ग्रेड के वाटर साल्यूवल उर्वरकों का क्रय किया जाना बताया गया, लेकिन दस्तावेज निरीक्षण दल को अवलोकन नही कराये गये, जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 उल्लंघन होने के कारण एनपीके 16:08:24 960 कि.ग्रा व एनपीके 19:19:19 660 कि.ग्रा उर्वरक के विक्रय को प्रतिबंधित किया गया।

कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि किसानों को खाद–बीज की किल्लत पैदा करने वाले, कालाबाजारी करने वाले या बिना वैध दस्तावेजों के अमानक उर्वरक/कीटनाशक औषधि विक्रय करने वाले कृषि केन्द्रों पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यदि भविष्य में कोई भी विक्रेता अथवा निर्माता द्वारा नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस निलंबित/निरस्त करने के साथ–साथ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सभी उर्वरक विक्रेताओं एवं समितियों को निर्देशित किया है कि किसानों को निर्धारित दर पर ही उर्वरक उपलब्ध कराएं तथा अधिक मूल्य वसूली की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। विभाग द्वारा खरीफ सीजन में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की सतत निगरानी की जा रही है। निर्धारित दर से अधिक दाम पर विक्रय किए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। किसान भाई किसी भी प्रकार की उर्वरक वितरण में अनियमितता पाये जाने पर इसकी शिकायत नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में कर सकते हैं। राज्य स्तरीय निरीक्षण दल- मंयक बघेल उप संचालक कृषि, हर्ष मिश्रा सहायक संचालक कृषि, जितेन्द्र ठाकुर सहायक संचालक कृषि एवं जिला स्तरीय निरीक्षण दल- संदीप कुमार भोई उप संचलाक कृषि दुर्ग, निलिमा राजपूत उर्वरक निरीक्षक सिरसा, सुनील सिंगौर ग्रा.कृ.वि.अ तथा पवन कुमार देवांगन ग्रा.कृ.वि.अ ने संयुक्त रुप से मिल कर उपरोक्त कार्यवाही की।

Since 1972
CROWN-TV®
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

उन्नत तकनीक से गन्ना खेती को मिलेगा नया आयाम

सूरजपुर। माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, केरता द्वारा सूरजपुर कलेक्टर रेना जमील के निर्देश पर गन्ना उत्पादक किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती की तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से क्षेत्र के विभिन्न गांवों में प्रशिक्षण एवं किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य गन्ना उत्पादन में वृद्धि, लागत में कमी तथा किसानों की आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है। कारखाना क्षेत्र के अंतर्गत सूरजपुर, बलरामपुर एवं सरगुजा जिले के 267 गांवों के गन्ना उत्पादक किसानों को उन्नत खेती की नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसानों को उन्नत किस्म के बीजों का चयन, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, जल संरक्षण एवं सिंचाई की वैज्ञानिक पद्धतियां, कीट एवं रोग नियंत्रण तथा बेहतर उत्पादन के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों की विस्तृत जानकारी विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जा रही है। ग्राम परसवार, मायापुर-1, बैकोना, पोडिया, बगड़ा, मायापुर-2, सुन्दरगंज, दुप्पी, रेवतपुर, कुंदीकला, अखोराखुर्द, टुकुडांड, पोपरंगा, महोरा, धरमपुर और रुखपुर सहित अन्य गांवों में आयोजित चौपालों में किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

हर दिन 8 घरों में लग रहे सोलर पैनल, अब तक 25.80 लाख रुपए की मुफ्त बिजली

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नवगठित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत एक बड़ी क्रांति देखने को मिल रही है। कलेक्टर के नेतृत्व में जिले में यह योजना रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। विभागीय तालमेल, बैंकर्स-वेंडर्स की सक्रियता और 'बिहान' छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला सदस्यों के मैदानी प्रचार-प्रसार के चलते जिले में हर दिन औसतन 8 घरों में सोलर सेटअप इंस्टॉल किए जा रहे हैं। विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता और जिले के ऊर्जा कर्मियों के कड़े परिश्रम से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मिले 4,312 कनेक्शनों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। पिछले तीन महीनों अप्रैल, मई और जून में ही जिले के घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और शासकीय-निजी कार्यालयों में 550 से अधिक सोलर सेटअप लगाए जा चुके हैं, जबकि 780 नए आवेदनों पर काम तेजी से चल रहा है।

सेवा सेतु के माध्यम से दो दिन में मिला आय प्रमाण पत्र

रायपुर। शासन की डिजिटल सेवाएं अब आम नागरिकों के लिए सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा का सशक्त माध्यम बन रही हैं। मुंगेली के लोक सेवा केंद्र (तहसील कार्यालय परिसर) में संचालित सेवा सेतु पोर्टल ने एक छात्रा के भविष्य को समय पर नई दिशा देने का कार्य किया। सुरीघाट निवासी राजेश्वरी निषाद को स्कूल में प्रवेश (एडमिशन) के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। प्रमाण पत्र नहीं मिलने की चिंता से परिवार परेशान था और प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी। इसी दौरान राजेश्वरी के पिता भगवत निषाद लोक सेवा केंद्र पहुंचे। वहां मौजूद सेवा सेतु के कर्मचारियों ने आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए। आवेदन का त्वरित निराकरण करते हुए महज दो दिनों के भीतर आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया।

बेहतर अध्ययन-अध्यापन, अनुशासन और समृद्ध संसाधनों से विद्यार्थियों की पहली पसंद बन रहा पीएम श्री विद्यालय

श्रीकंचनपथ न्यूज

सूरजपुर। सूरजपुर जिले में संचालित पीएम श्री शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जयनगर ने शिक्षा, खेल एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित कर न केवल जिले, बल्कि प्रदेश स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हाल ही में राजधानी रायपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान विद्यालय को राज्य स्तरीय प्रदर्शन मूल्यांकन में शीर्ष पाँच पीएम श्री विद्यालयों में शामिल किया गया, जो जिले के लिए गौरव का विषय है।

विद्यालय में कक्षा पहली से बारहवीं तक लगभग 610 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

यहां सभी कक्षाओं के लिए पृथक कक्ष, स्मार्ट बोर्ड आधारित शिक्षण व्यवस्था, आधुनिक भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय तथा कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों को व्यवहारिक अध्ययन कराया जाता है, वहीं पुस्तकालय में साहित्यिक पुस्तकों के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। विद्यालय परिसर में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय तथा स्वच्छता की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

विद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ-साथ अनुशासन, संस्कार और समग्र व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित भोजन मंत्र, राज्य गीत, राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत का गायन विद्यालय में नियमित रूप से कराया जाता है। विद्यालय प्रारंभ होने से पूर्व, मध्यान्ह भोजन के समय तथा विद्यालय की छुट्टी के समय इनका सामूहिक गायन विद्यार्थियों में अनुशासन, देशभक्ति, सांस्कृतिक चेतना और नैतिक मूल्यों के संवर्धन का माध्यम बन रहा है। विद्यालय की गुणवत्ता का ही परिणाम है कि कई विद्यार्थी निजी विद्यालयों से नाम कटवाकर यहां प्रवेश ले रहे हैं। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के अनुसार यहां अध्ययन-अध्यापन का वातावरण बेहतर है तथा स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर शिक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल गतिविधियों से सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी, व्यावहारिक और रोचक बनी है।

खेल गतिविधियों के लिए विद्यालय में उत्तम खेल मैदान उपलब्ध है, जहां विभिन्न खेलों का नियमित अभ्यास और संचालन किया जाता है। विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 02 स्वर्ण, 10 रजत और 27 कांस्य पदक अर्जित किए हैं। वहीं सात्विक राज का चयन ड्यूस क्रिकेट तथा आरुष मृदा का चयन नेशनल गेम्स के लिए हुआ। सरगुजा ओलंपिक में विद्यालय के विद्यार्थियों ने बास्केटबॉल प्रतियोगिता में तृतीय स्थान, जबकि शिक्षकों की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

शैक्षणिक उपलब्धियों में भी विद्यालय लगातार उत्कृष्ट रहा है। पीएम श्री विद्यालय के रूप में उन्नयन के बाद से विद्यालय का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा है। बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं के 02 तथा 12वीं के 6 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किए हैं।

निर्माण कार्यों का हर 15 दिनों में करें निरीक्षण, नागरिक सुविधाओं के काम में न हो लापरवाही : शंगीता आर.

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव शंगीता आर. ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ रायपुर नगर निगम के अधिकारियों की बैठक लेकर राजधानी रायपुर में विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर नगर निगम मुख्यालय में आयोजित बैठक में तकनीकी कारणों से लंबित अप्रारंभ कार्यों की बाधाएं दूर कर उन्हें तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जोन कमिश्नरों को हर 15 दिनों में कार्यस्थलों का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक आर. एक्का और रायपुर नगर निगम के आयुक्त संबित मिश्रा भी बैठक में मौजूद थे।

सचिव शंगीता आर. ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि राजधानी में नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट तथा अन्य बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए सभी जोन कमिश्नरों, स्वच्छ भारत मिशन के वार्ड प्रभारियों और नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारियों का गंभीरता एवं जवाबदेही के साथ निर्वहन करने को कहा।

नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव ने शहर के जलभराव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर व्यापक सफाई अभियान चलाने तथा जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी नियमित एवं प्लेसमेंट अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्धारित समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने से कार्यक्षमता और सेवा वितरण दोनों बेहतर होते हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के आवासों के निर्माण में तेजी लाने को कहा। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की समीक्षा के दौरान रायपुर की स्वच्छता रैंकिंग को सुधारने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने को कहा।

सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने राजधानी की गरिमा के अनुरूप स्वच्छता व्यवस्था विकसित करने, शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने तथा कचरा परिवहन की व्यवस्था की नियमित निगरानी व समीक्षा करने को कहा। उन्होंने नालंदा परिसर की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पाण्डेय, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य, मुख्य अभियंता राजेश शर्मा और रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक एस.के. सुन्दरानी सहित नगर निगम के सभी अपर आयुक्त, उपायुक्त, जोन कमिश्नर, अभियंता, सभी विभागों के प्रभारी अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन के वार्ड प्रभारी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी तथा जोन सहायक राजस्व अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

किसानों के लिए बड़ी राहत : अब खरीफ सीजन में पिछले वर्ष के बराबर मिलेगा यूरिया

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने यूरिया वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब किसानों को खरीफ 2025 में प्राप्त यूरिया की मात्रा के बराबर खरीफ 2026 में भी यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पूर्व लागू 80 प्रतिशत वितरण सीमा समाप्त कर दी गई है, जिससे किसानों को खेती के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।

जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने दुलदुला स्थित आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का निरीक्षण कर खाद-बीज की उपलब्धता, कृषि ऋण वितरण एवं किसानों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने किसानों को नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी समय समिति में यूरिया का स्टॉक कम होने के कारण पूरी पात्रता के अनुसार उर्वरक नहीं मिल पाता है, तो स्टॉक उपलब्ध होते ही शेष मात्रा भी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे किसानों को उर्वरक की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सहकारी समिति में उपलब्ध खाद-बीज के भंडारण, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वितरित कृषि ऋण तथा किसानों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीफसीजन में किसानों को खाद, बीज एवं कृषि ऋण समय पर उपलब्ध कराया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो। कलेक्टर व्यास ने समिति में पहुंचे किसानों से सीधे संवाद कर खेती की तैयारियों, उर्वरकों की उपलब्धता एवं कृषि संबंधी समस्याओं की जानकारी ली तथा अधिकारियों को उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एवं नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि इन उर्वरकों के उपयोग से फसलों को संतुलित पोषण मिलता है।

बंदूक छोड़ विकास की राह चुनी, शासकीय योजनाओं ने बदली मड़कम भीमा की जिंदगी

पक्का घर, रोजगार और सम्मान के साथ मुख्यधारा में लौटे, बने आत्मनिर्भर जीवन की मिसाल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। सुकमा जिले में शासन की पुनर्वास नीति और जनकल्याणकारी योजनाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। कोंटा विकासखंड के ग्राम पंचायत पोलमपल्ली के निवासी मड़कम भीमा इसकी प्रेरक मिसाल हैं। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास और लोकतंत्र की मुख्यधारा को अपनाया। जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों के सहयोग से आज वे सम्मान के साथ सामान्य जीवन जी रहे हैं।

मुख्यधारा में लौटने के बाद जिला प्रशासन ने मड़कम भीमा को विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत उन्हें पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिली। अब उनका परिवार सुरक्षित और सम्मानजनक घर में रह रहा है। इस योजना ने उनके जीवन में स्थिरता और भविष्य के प्रति नया विश्वास पैदा किया।

मड़कम भीमा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। उन्होंने गांव के विकास कार्यों में मेहनत से काम किया और मजदूरी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त हुई। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और आत्मविश्वास भी बढ़ा।

आज मड़कम भीमा अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं। वे मानते हैं कि शासकीय योजनाओं और जिला प्रशासन के सहयोग ने उन्हें नई पहचान और नया जीवन दिया है। अब वे विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए अपने परिवार का बेहतर भविष्य बना रहे हैं।

मड़कम भीमा की सफलता की कहानी बताती है कि शासन की पुनर्वास नीति और जनकल्याणकारी योजनाएं लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही हैं। यह कहानी युवाओं को संदेश देती है कि हिंसा का रास्ता छोड़कर शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता का मार्ग अपनाने से जीवन में नई शुरुआत संभव है। शासन समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़ा है।

'डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम' से खेत से लेकर सोशल मीडिया तक सशक्त होगा किसान : दक्ष वैद्य साहू

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सोशल मीडिया प्रदेश सहप्रभारी दक्ष वैद्य साहू ने कहा कि भाजपा का डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' एवं 'तकनीक-संपन्न किसान' के विजन को धरातल पर उतारने वाला एक दूरदर्शी अभियान है।

यह कार्यक्रम किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाकर गांव-गांव तक पार्टी की रीति-नीति और सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। श्री साहू ने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर के नेतृत्व में किसान कल्याण को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने का जो संकल्प लिया गया है, उसी तर्ज पर किसान मोर्चा भी अपने प्रत्येक पदाधिकारी एवं बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को डिजिटल प्रशिक्षण से जोड़ेगा। हमारा लक्ष्य है कि खेत में हल चलाने वाला किसान और सोशल मीडिया पर विचार रखने वाला कार्यकर्ता, दोनों एक साथ डिजिटल रूप से सशक्त हों। श्री दक्ष वैद्य साहू ने कहा कि आज एमएसपी, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, ड्रोन तकनीक और प्राकृतिक खेती जैसी दर्जनों योजनाएं केंद्र व राज्य सरकार चला रही है। लेकिन जब तक ये जानकारियां समय पर किसान तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। डिजिटल प्रशिक्षण से किसान मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता 'डिजिटल प्रचारक' बनकर इन योजनाओं को मोबाइल के माध्यम से हर खेत-खलिहान तक पहुंचाएगा। साथ ही विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का भी तथ्यों के साथ त्वरित खंडन कर सकेगा।

'डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम' महिला शक्ति को डिजिटल युग में सशक्त बनाने की क्रांतिकारी पहल : रत्नावली कौशल

श्रीकंचनपथ न्यूज

मुंगेली। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं छत्तीसगढ़ शासन के अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की पूर्व सदस्य रत्नावली कौशल ने कहा कि भाजपा द्वारा प्रारंभ किया गया डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'डिजिटल इंडिया' के विजन को साकार करने वाला और महिला कार्यकर्ताओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने वाला एक ऐतिहासिक अभियान है। रत्नावली कौशल ने बताया कि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी के मार्गदर्शन में इस विशेष प्रशिक्षण अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने की संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक 'बूथ सखी' डिजिटल रूप से प्रशिक्षित होकर पार्टी की विचारधारा, इतिहास, नेतृत्व की पंचनिष्ठा और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाए।

रत्नावली कौशल ने कहा कि आज का युग सूचना का युग है। त्वरित जानकारियां, राष्ट्रीय मुद्दे और जनहित के विषय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही आमजन तक पहुंचते हैं। ऐसे में भाजपा महिला मोर्चा की प्रत्येक कार्यकर्ता का डिजिटल क्षेत्र में दक्ष होना समय की मांग है। इससे न केवल संगठन मजबूत होगा, बल्कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुंच सकेगा।

सहकारिता मंत्री ने 'सहकार संकल्प दौड़' को दिखाई हरी झंडी

सहकारिता एक नारा नहीं, बल्कि जन-आंदोलन है : केदार कश्यप

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को नई दिशा मिल रही है। इसी कड़ी में सहकारिता विभाग द्वारा राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में 'सहकार संकल्प दौड़' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि सहकारिता केवल एक नारा नहीं, बल्कि जन-आंदोलन है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा रहा है।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता को जन-जन तक पहुंचाने और लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने जो संकल्प लिया था, उसे पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सहकारिता विभाग ने विगत ढ़ाई वर्ष में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता सप्ताह को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया गया है, प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को अधिक सक्षम बनाया जा रहा है, किसानों को समय पर ऋण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। साथ ही सहकारिता के दायरे का विस्तार कर युवाओं, महिलाओं और ग्रामीणों को स्वरोजगार एवं आजीविका के नए अवसरों से जोड़ा जा रहा है।

इस वर्ष की दौड़ सहकारिता की भावना के साथ, एक कदम समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर थीम पर आयोजित की गई। इसका उद्देश्य लोगों में सहयोग, एकता, स्वस्थ जीवनशैली और सामूहिक विकास का संदेश पहुंचाना था। सहकार संकल्प दौड़ सुबह 6 बजे तेलीबांधा मरीन ड्राइव से शुरू हुई। इसमें प्रदेशभर से युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्थाओं के सदस्य, महिला समूहों और विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

दौड़ में पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान बेमेतरा के ओंकार वर्मा, द्वितीय अमलेश्वर के करण साहू और तृतीय स्थान परखेमराज सोनकर रहे। इसी तरह महिला वर्ग में प्रथम मीरा साहू, द्वितीय पूर्णिमा साहू और तृतीय स्थान पर शिबू वर्मा रही। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः पांच हज़ार, तीन हज़ार और दो हजार रूपए का नगद पुरस्कार प्रदान कियागया।

इस पहल से युवाओं और आम नागरिकों में खेल तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यह दौड़ केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सहकारिता, स्वास्थ्य और सामाजिक सहभागिता का जन-जागरूकता अभियान है। इसका उद्देश्य सहकारिता से समृद्धि, साथ चलें, साथ बढ़ें और स्वस्थ समाज, समृद्ध प्रदेश के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना है।

दादू-नानू की याद आ गई, मैं वापस आऊंगा देखने के बाद इमोशनल हुई कृति खरबंदा

एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने इम्तियाज़ अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल नोट शेयर किया है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म ने उन्हें भीतर तक छू लिया और उनके दिवंगत दादाजी और नानाजी की यादें ताज़ा कर दी हैं।

फिल्म से जुड़ी अपनी इमोशंस शेयर करते हुए कृति ने लिखा है कि इस फिल्म को उन्हें अपने दादू और नानू दोनों की याद आ गई। उन्होंने कहा कि वो उन्हें हर दिन याद करती हैं, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें रुककर उनके सभी त्यागों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जो पिछली पीढ़ियों ने किए थे। उन्होंने लिखा कि हम अक्सर जिस ज़मीन पर खड़े होते हैं, उसे अपना मान लेते हैं, बिना ये समझे कि शायद किसी ने वहां तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी दुनिया पीछे छोड़ दी होगी।

विशेष रूप से डायरेक्टर इम्तियाज़ अली को संबोधित करते हुए कृति ने लिखा है, आपकी फिल्में अक्सर घर जैसी लगती हैं। इस बार घर नहीं मिला इस बार घर की याद मिल गई। उनके इन शब्दों ने खूबसूरती से ये एहसास बयां किया कि फिल्म ने सिर्फ घर की कहानी नहीं दिखाई, बल्कि घर की गहरी याद और उससे जुड़ी इमोशंस को जगा दिया है।

कृति ने आगे लिखा कि मैं वापस आऊंगा देखने के बाद घर का अर्थ उनके लिए पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने लिखा है, शायद घर सिर्फ वो जगह नहीं होती जहां हम रहते हैं। कभी-कभी घर वो भी होता है, जहां हम कभी वापस नहीं जा पाते। उनके अनुसार, घर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी इमोशन भी हो सकता है, जो हमेशा हमारी यादों में जीवित रहती है, भले ही वहां लौट पाना संभव न हो।

कृति ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि इसका प्रभाव इसकी अवधि से कहीं अधिक बड़ा है। उन्होंने लिखा कि कुछ कहानियां पर्दा गिरने के साथ खत्म नहीं होतीं, बल्कि दर्शकों के साथ उनके घर तक जाती हैं और लंबे समय तक उनके दिलों में बस जाती हैं।

अपने इमोशंस मैसेज के अंत में कृति ने फिल्म की पूरी टीम का धन्यवाद भी किया है कि उन्होंने एक आम इंसान को नायक के रूप में प्रेजेंट किया है। उन्होंने अपना आभार अपने दादू, नानू और उन जैसे अनगिनत लोगों को समर्पित करते हुए लिखा है, शुक्रिया मेरे दादू और नानू जैसे उन सभी आम आदमी को हीरो बनाने के लिए। इसी के साथ उन्होंने अपने इस मैसेज का समापन दिल वाले इमोजी के साथ किया है।

कृति खरबंदा का ये इमोशनली मैसेज सोशल मीडिया पर फैंस के दिलों को छू रहा है और ये दिखाता है कि मैं वापस आऊंगा ने दर्शकों पर कितना गहरा इमोशनल प्रभाव छोड़ा है।

'लोग मुझसे सिर्फ टीआरपी चाहते हैं'

'बिग बॉस 19' के बाद रियलिटी शो नहीं करना चाहती थीं तान्या मित्तल

बिग बॉस 19 में हिस्सा लेने के बाद एंटरप्रेन्योर और रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी तान्या मित्तल घर-घर में जानी-पहचानी हस्ती बन गईं। हालांकि, इस लोकप्रियता की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। सलमान खान की होस्टिंग वाले शो में मिले अनुभव की वजह से वह दोबारा रियलिटी शो की दुनिया में लौटने को लेकर हिचकिचाने लगी थीं। उनका कहना है कि मुझे लगा कि लोग मुझसे सिर्फ टीआरपी चाहते थे, चाहे मुझे नीचा दिखाकर या उकसाकर।

मां के कहने पर किया 'मां है ना' शो

कैसे उनकी मां ने उन्हें दोबारा रियलिटी शोज में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि मैंने मन बना लिया था कि अब कोई और रियलिटी शो नहीं करूंगी। पर मां ने मुझसे कहा, 'अगर तुम चीजों से भागती रहोगी, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी।

अपने डर का सामना करो और इस बार मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी' इसके बाद ही तान्या ने रियलिटी शो 'मां है ना' के लिए हां बोला। तान्या ने कहा कि 'मां है ना' की शूटिंग के दौरान एक समय ऐसा आया जब वह शो छोड़ना चाहती थीं, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी मां को भी उसी तरह की नफरत का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वह खुद गुज़र चुकी थीं।

मैं मानसिक रूप से शो से ऊब चुकी थी। मैं इसे जारी नहीं रखना चाहती थी। लेकिन मेरी मां ने मुझे हार मानने नहीं दिया और मुझे याद दिलाती रहीं कि भागने से लोगों की बातें कभी बंद नहीं होंगी।

चुप्पी सबसे शक्तिशाली हथियार

ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर तान्या का कहना है कि चुप्पी सबसे शक्तिशाली हथियार है। लोग मेरी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझसे ज्यादा सवाल किसी और से नहीं पूछे जाते, फिर भी मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही हूं।

अगर कोई मुझे बेरोजगार कहता है या दिखावा करने का आरोप लगाता है, तो मुझे जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होती। मेरी जिंदगी का मकसद उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। मुझे एहसास हुआ है कि लोगों के लिए मुझे पचा पाना मुश्किल है। लोगों को महिलाओं को इस तरह जीते हुए देखने की आदत नहीं है। उन्होंने पुरुषों को ऐसा करते देखा है, लेकिन महिलाओं को नहीं।

लोगों के दोहरे मापदंड पर तान्या ने कसा तंज

दोहरे मापदंडों की ओर इशारा करते हुए तान्या ने कहा कि जब किसी पुरुष के पास मर्सिडीज या बॉडीगार्ड होते हैं, तो कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन जब कोई महिला ऐसा करती है, तो लोग तुरंत पूछते हैं कि क्या यह गाड़ी उसके पिता की है या किसी और की। मैं ऐसी इंसान नहीं हूं जो टीआरपी या काम के लिए बेताब रहती हो। बिग बॉस के बाद मैंने कई ऑफर ठुकरा दिए क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स करना चाहती हूं जो मेरी इमेज को बेहतर बनाएं।

मां इंटि बंगारम ने तोड़ा 17 साल पुराना रिकॉर्ड बनी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल लीड तेलुगू फिल्म

सामंथा रुथ प्रभु ने बॉक्स ऑफिस पर वो कर दिखाया है, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। उनकी हालिया रिलीज फिल्म मां इंटी बंगारम सिनेमाघरों में ऐसी आंधी लाई कि तेलुगू सिनेमा का 17 साल पुराना एक महा-रिकॉर्ड ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इसने अनुष्का शेट्टी की साल 2009 की ब्लॉकबस्टर अरुंधति को पछाड़कर इतिहास रच दिया है। अब सामंथा की ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलूगू महिला प्रधान फिल्म बन गई है। सामंथा की फिल्म मां इंटी बंगारम से पहले अनुष्का शेट्टी की 2009 में आई फिल्म अरुंधति को तेलुगू सिनेमा में महिला-प्रधान फिल्मों के लिए सबसे बड़ा पैमाना माना जाता था। उस दौर में, जहां सिर्फ अभिनेताओं का बोलबाला था, अनुष्का ने अपनी दमदार और अनोखी भूमिकाओं से इंडस्ट्री में एक खास पहचान बनाई थी, लेकिन अब सामंथा की मां इंटी बंगारम ने अनुष्का के उस 17 साल पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पूरी तरह से तोड़ दिया है।

सामंथा की ये फिल्म 19 जून को रिलीज हुई थी। इसने दुनियाभर में 83 करोड़ और भारत में 50 करोड़ की बंपर कमाई कर ली है। इसके साथ ही ये तेलुगू सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला-प्रधान फिल्म बन गई है। सामंथा के प्रोडक्शन हाउस त्रालाला मूविंग पिक्चर्स ने इस ऐतिहासिक सफलता की पुष्टि की है, जिसके बाद से प्रशंसक बेहद गर्व के साथ सामंथा को क्वीन और सुपरस्टार कहकर बधाई दे रहे हैं।

कोडी रामकृष्ण की फिल्म अरुंधति ने अनुष्का शेट्टी के दम पर दुनियाभर में 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर लंबे समय तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला-प्रधान तेलुगू फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम रखा। अब मां इंटी बंगारम ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि, महानटी ने 75 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी, लेकिन उसमें कीर्ति सुरेश के साथ दुलकर सलमान, सामंथा और विजय देवरकोंडा समेत कई बड़े सितारे भी अहम भूमिकाओं में थे।

'हमें टाइटल से आपत्ति नहीं', श्रद्धा कपूर की 'ईठा' को मिला विठाबाई नारायणगांवकर की बेटी का समर्थन

मशहूर लावनी और तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर पर बन रही फिल्म 'ईठा' के टाइटल को लेकर हाल ही में विवाद खड़ा हो गया था, जब दिवंगत कलाकार के परिवार के एक सदस्य ने इस पर आपत्ति जताई। हालांकि, अब विठाबाई की सबसे बड़ी बेटी ने परिवार का पक्ष साफ करते हुए कहा है कि उन्हें फिल्म के टाइटल से कोई दिक्कत नहीं है। फिल्म के टाइटल को लेकर हुए विवाद पर बात करते हुए विठाबाई की सबसे बड़ी बेटी मंगला बनसोडे करावडीकर ने चिंताओं को खारिज कर दिया। ई-टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें फिल्म के टाइटल से कोई दिक्कत नहीं है।

मैंने मोहित से बात की है और उनसे कहा है कि वे इस बारे में आगे कोई बयान न दें। यह टाइटल सही है क्योंकि उन दिनों, जिन गांवों में मेरी मां परफॉर्म करती थीं, वहां के लोग अक्सर उन्हें 'ईठा' कहकर बुलाते थे। मैंने फिल्म के डेवलपमेंट के दौरान डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के साथ यह जानकारी शेयर की थी।

फिल्म बनने पर जताई खुशी

मंगला ने आगे कहा कि मैं सात साल की उम्र से ही स्टेज पर परफॉर्म कर रही हूं और मैंने लोगों को अपनी मां को उस नाम से बुलाते हुए सुना है। बायोपिक पर खुशी जाहिर करते हुए मंगला ने कहा कि हमें खुशी है कि इस फिल्म के जरिए लोग मेरी मां के बारे में जान पाएंगे और यह भी कि वह अपनी कला के प्रति कितनी समर्पित थीं। आने वाली इस फिल्म का टाइटल तब चर्चा का विषय बन गया जब खबरों में कहा गया कि विठाबाई के पोते मोहित नारायणगांवकर ने 'ईठा' नाम पर आपत्ति जताई और मांग की कि टाइटल में दिवंगत कलाकार का पूरा नाम शामिल किया जाए। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के फिल्म और संस्कृति विभाग ने भी फिल्म बनाने वालों से टाइटल पर फिर से विचार करने को कहा, साथ ही यह भी साफ किया कि उन्हें फिल्म से कोई आपत्ति नहीं है। लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित 'ईठा' 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

कौन थी विठाबाई नारायणगांवकर?

विठाबाई नारायणगांवकर महाराष्ट्र की सबसे मशहूर तमाशा कलाकारों में से एक थीं। उन्हें 1957 और 1990 में भारत के राष्ट्रपति से मेडल मिले और महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें 'तमाशा सम्राज्ञी' के सम्मान से नवाजा।

बंद नाक को खोलने में कारगर है नीलगिरी का भाप लेना, ऐसे करें इस्तेमाल

नीलगिरी का तेल कैसे काम करता है?

नीलगिरी का तेल एक प्राकृतिक उपाय है, जो रक्त नलिकाओं को सिकोड़कर सूजन को कम करता है। इससे नाक की सूजन भी कम होती है और सांस लेना आसान हो जाता है। इसके अलावा नीलगिरी के तेल में सूजन कम करने वाले तत्व भी होते हैं। जब आप नीलगिरी का भाप लेते हैं तो यह आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है, जिससे आपको राहत मिलती है।

भाप लेने का तरीका

नीलगिरी का भाप लेने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें 5-6 बूंदें नीलगिरी का तेल डालें। अब अपने सिर को तौलिये से ढककर बर्तन के ऊपर रख लें ताकि भाप आपके चेहरे पर सीधे आए। ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न हो ताकि आपकी त्वचा जल न जाए। इस प्रक्रिया को 10-15 मिनट तक दोहराएं। इससे आपकी बंद नाक खुल जाएगी और आपको राहत मिलेगी।

अन्य लाभ

नीलगिरी का भाप लेने से केवल बंद नाक ही नहीं बल्कि सिरदर्द, थकान और तनाव में भी राहत मिलती है। इसके अलावा यह आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि भाप लेने से त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं और गंदगी बाहर निकल जाती है। नीलगिरी का तेल एक प्राकृतिक उपाय है, जो बिना किसी दवा के आपको ताजगी और राहत प्रदान करता है। इसे नियमित रूप से अपनाकर आप अपनी सेहत में सुधार ला सकते हैं।

सावधानियां बरतें

नीलगिरी का भाप लेते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील होती है तो पहले थोड़ा परीक्षण करें। इसके अलावा अगर आपको सांस की या किसी अन्य बीमारी हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बच्चों और बुजुर्गों को भी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि उनकी त्वचा अधिक संवेदनशील होती है। इस प्रकार नीलगिरी का भाप लेना एक सरल और असरदार उपाय हो सकता है, जो आपकी बंद नाक को खोलने में मदद करता है।

शाहिद कपूर ने इस शहर में शूटिंग से किया इनकार!

प्रदूषण के चलते लिया फैसला, 'कॉकटेल 2' से जुड़ा बड़ा खुलासा

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिले हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा है।

खराब हवा के कारण शूटिंग से किया इनकार

फिल्म की शूटिंग जहां इटली जैसी खूबसूरत लोकेशन पर हुई, वहीं दिल्ली-एनसीआर में शूटिंग का अनुभव काफी अलग और मुश्किल भरा रहा। एक शेड्यूल के दौरान टीम को खतरनाक स्तर के प्रदूषण में काम करना पड़ा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 के पार पहुंच गया था।

लाइन प्रोड्यूसर सुमित त्यागी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में इस अनुभव को याद किया। उन्होंने बताया कि खराब हवा के कारण शाहिद कपूर ने एक समय पर बाहर निकलकर शूट करने से मना कर दिया था। सुमित ने शाहिद को 'मनमौजी' भी बताया।

5-6 एयर प्यूरीफायर का किया इंतजाम

सुमित ने कहा कि टीम को बताया गया कि शाहिद इतनी खराब हवा में शूट नहीं करना चाहते। इसके बाद प्रोडक्शन टीम ने उनके लिए 5-6 एयर प्यूरीफायर का इंतजाम किया, जबकि शूट पूरी तरह आउटडोर था। यह शूट गुरुग्राम के साइबर सिटी में हो रहा था।

उन्होंने कहा, 'हमें समझ नहीं आ रहा था कि खुले में एयर प्यूरीफायर कैसे काम करेंगे, लेकिन हमें बताया गया कि यह सिर्फ संतुष्टि के लिए है।'

शाहिद का सावधानी बरतना सही था

सुमित ने आगे कहा, 'यह उन चीजों में से था जो आखिरी वक्त पर खरीदी गईं। हमने तुरंत किसी को भेजकर ये मंगवाए। शाहिद ने कहा था कि वो वैन से बाहर नहीं निकलेंगे। वो सिर्फ शॉट के समय मास्क हटाते थे, बाकी समय उन्होंने मास्क ही पहना हुआ था। साइबर सिटी जैसे खुले इलाके में एयर प्यूरीफायर का कोई खास फायदा नहीं था।'

हालांकि सुमित ने यह भी माना कि उस समय प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक था, इसलिए शाहिद का सावधानी बरतना सही था। लेकिन उनका कहना था कि आउटडोर शूट के लिए एयर प्यूरीफायर लाना सिर्फ एक दिखावे जैसा कदम था, ताकि एक्टर को लगे कि उनकी बात को गंभीरता से लिया गया है। वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहिद कपूर जल्द ही 'फर्जी सीजन 2' में नजर आने वाले हैं।

खास खबर

दिव्यांग बच्चों के लिए बलरामपुर में लगा विशेष यूडीआईडी कैंप

रायपुर। प्रदेश में दिव्यांग बच्चों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष यूडीआईडी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में जिला अस्पताल परिसर में विशेष यूडीआईडी कैंप का आयोजन किया गया। कलेक्टर के निर्देशन में आयोजित इस विशेष शिविर का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। जिला चिकित्सालय में आयोजित शिविर में जिले के विभिन्न विकासखंडों से पहुंचे 57 बच्चों का विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक चिकित्सकीय मूल्यांकन किया गया। परीक्षण उपरांत पात्र बच्चों को नियमानुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड जारी किए गए।

बड़ी राहत : आवाजाही के लिए खुला तान नदी ब्रिज

रायपुर। कटघोरा से अंबिकापुर के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के कटघोरा-शिवनगर खंड पर गुरसियाँ स्थित तान नदी ब्रिज को मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद आम यातायात के लिए पुनः खोल दिया है। परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बिलासपुर के परियोजना निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए ब्रिज की आवश्यक संरचनात्मक मरम्मत रिकॉर्ड समय में पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही इस मार्ग पर यातायात पुनः पूर्ण क्षमता के साथ सुरक्षित एवं सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है। पुल की रेलिंग के बचे कार्य को कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।

किसानों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने की पहल

रायपुर। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की स्थापना के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जशपुर जिले में 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक सहकारी सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न जनहितकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत सरकार एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार आयोजित इस सप्ताह का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाना, किसानों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना तथा सहकारी संस्थाओं की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाना है। सहकारी सप्ताह के तहत 2 जुलाई को जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान किसानों एवं समिति सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), रूपे केसीसी कार्ड तथा माइक्रो एटीएम कार्ड वितरित किए गए। इससे किसानों को बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच, डिजिटल भुगतान की सुविधा तथा कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सेवाओं का लाभ अधिक सुगमता से मिल सकेगा। कार्यक्रम के दौरान किसानों, जनप्रतिनिधियों एवं समिति सदस्यों को मॉडल पैक्स का भ्रमण भी कराया गया।

देवभूमि और छत्तीसगढ़ के बीच बढ़ा वैचारिक सेतु

मुख्यमंत्री धामी से मिले छत्तीसगढ़ के मीडिया प्रतिनिधि

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री निवास (देहरादून) में छत्तीसगढ़ के मीडिया प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक अत्यंत गरिमामय और सौजन्य भेंट हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने छत्तीसगढ़ की मीडिया टीम और अधिकारियों के साथ अपने अनुभव साझा किए और उत्तराखंड के बहुआयामी विकास, सांस्कृतिक धरोहर तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे अभूतपूर्व कार्यों की जानकारी दी।

मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार विकास भी, विरासत भी के मूल मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि नैनीताल, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों के लिए अलग-अलग विकास प्राधिकरणों का गठन कर उनके विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों का संतुलित सामाजिक, आर्थिक और नैसर्गिक विकास करना है, ताकि यहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा सके।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने जोर देकर कहा कि उत्तराखंड ऋषियों, मुनियों और संतों की पावन तपोस्थली है। इस देवभूमि की आध्यात्मिक पहचान को संभालना हम सभी का परम दायित्व है। उन्होंने नैसर्गिक संपदा (प्राकृतिक संसाधनों) के संरक्षण पर विशेष बल दिया, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण संजोकर रखा जा सके।

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने में छत्तीसगढ़ सरकार की भूमिका अनुकरणीय: संवाद के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की दूरगामी सोच की जमकर सराहना की। उन्होंने सीएम साय की मंशानुरूप इस महत्वपूर्ण भ्रमण कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और संयुक्त सचिव सह आयुक्त जनसंपर्क रजत बंसल को विशेष रूप से बधाई दी।

श्री धामी ने इस बात को रेखांकित किया कि देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ (मीडिया) की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने और पत्रकार कल्याण से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य रहा है। अधिकारियों के कुशल नेतृत्व में ऐसे अंतर्राज्यीय भ्रमणों से दोनों राज्यों के बीच वैचारिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को एक नया आयाम मिलता है।

अगले वर्ष हरिद्वार कुंभ के लिए विशेष आमंत्रण

भेंट के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छत्तीसगढ़ के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों के मीडिया दल को अगले वर्ष हरिद्वार में आयोजित होने वाले भव्य महाकुंभ के लिए सस्नेह आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री धामी ने एक बड़ा दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा कि कुंभ के पावन अवसर पर देश के सभी राज्यों के मीडिया प्रतिनिधियों को एक-एक अवसर दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस पहल से देश भर की मीडिया देवभूमि की पावन तपोभूमि, आध्यात्मिक ऊर्जा और वहां की विश्वस्तरीय व्यवस्थाओं को अपनी आँखों से देख सकेगी और इन अद्भुत अनुभवों को अपने-अपने राज्यों की जनता तक पहुँचा सकेगी।

एक अनूठा संगम

छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, खनिज व नैसर्गिक संपदा और उत्तराखंड की हिमालयी दिव्यता व आध्यात्मिक चेतना के बीच हुआ यह संवाद आने वाले समय में अंतर्राज्यीय समन्वय और राष्ट्रीय एकता का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरेगा। इस भ्रमण दल में मुख्यमंत्री धामी से मिलने वालों में दुर्ग,रायपुर,कोरबा,जगदलपुर,बिलासपुर,राजनांदगांव,कोरिया और धमतरी जिले के मीडिया प्रतिनिधी और छत्तीसगढ़ जनसंपर्क संचालनालय के अधिकारियों के साथ उत्तराखंड के सूचना एवं जनसंपर्क के निदेशक बंशीधर तिवारी,मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव पांडे,संयुक्त संचालक के.एस. चौहान सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कौशल विकास से बंदियों के पुनर्वास को नई दिशा

प्रदेश के जिला जेलों में बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल को मिल रही गति

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्य में बंदियों के पुनर्वास, कौशल उन्नयन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में जिला जेल सूरजपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) द्वारा 12 दिवसीय कौशल विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 35 बंदियों को अगरबत्ती निर्माण एवं साबुन निर्माण का व्यावहारिक, तकनीकी एवं उद्यमिता आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य बंदियों को रोजगारपरक कौशलों से सशक्त बनाते हुए रिहाई के उपरांत सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने के लिए सक्षम बनाना है। कार्यक्रम के माध्यम से बंदियों को उत्पादन आधारित गतिविधियों से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर बनने के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सकारात्मक जीवन की नई शुरुआत कर सकें।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को अगरबत्ती एवं साबुन निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है, जिसमें कच्चे माल का चयन, उत्पादन तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण, मशीनों एवं उपकरणों का सुरक्षित उपयोग, आकर्षक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन, लागत निर्धारण तथा लघु उद्योग स्थापना से संबंधित विषय शामिल हैं। इसके साथ ही बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय साक्षरता, बचत, ऋण सुविधाओं, सरकारी स्वरोजगार योजनाओं तथा उद्यमिता विकास संबंधी पहलुओं पर भी विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों में तकनीकी दक्षता के साथ-साथ आत्मविश्वास, अनुशासन, समय प्रबंधन, टीम भावना और स्वावलंबन की भावना विकसित करना है, ताकि वे रिहाई के पश्चात स्वयं का रोजगार स्थापित कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकें। जेल प्रशासन के अनुसार कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों के पुनर्वास की दिशा में प्रभावी पहल साबित हो रहे हैं। ऐसे प्रयास बंदियों को नया जीवन प्रारंभ करने का अवसर प्रदान करते हैं तथा उन्हें समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। आरएसईटीआई के अधिकारियों ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। इसी उद्देश्य के अनुरूप विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित संचालन किया जा रहा है, जिनके माध्यम से युवाओं, महिलाओं एवं विशेष वर्गों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है।

धान की खेती रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुवाई पर दे विशेष जोर

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। खरीफ सीजन 2026 में अल-नीनो के संभावित प्रभाव के कारण मानसून के देर से आने, जल्दी समाप्त होने तथा फसल अवधि के दौरान लंबे अंतराल तक वर्षा नहीं होने (खण्ड वर्षा) एवम् अल्प की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं कृषि मंत्र रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए सामान्य आकस्मिक कार्ययोजना तैयार की है। इस कार्ययोजना का उद्देश्य कम वर्षा की स्थिति में भी किसानों की फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उत्पादन बनाए रखना तथा खेती की लागत कम करना है।

कृषि विभाग द्वारा किसानों को कम एवं मध्यम अवधि में पकने वाली फसलों एवं किस्मों का चयन करने की सलाह दी गई है, ताकि वर्षा की अनिश्चितता का प्रभाव कम किया जा सके। धान की खेती में रोपा पद्धति के बजाय धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया है। इस तकनीक से 20 प्रतिशत पानी की बचत होती है, प्रति एकड़ लगभग 5,000 रुपये की लागत कम आती है तथा फसल 12 से 15 दिन पहले तैयार हो जाती है। कम वर्षा की संभावना को देखते हुए उच्चहन भूमि में धान के स्थान पर अरहर, मूंग एवं उड़द जैसी दलहनी तथा मूंगफली, तिल, रामतिल एवं सोयाबीन जैसी तिलहनी फसलों की खेती अपनाने की सलाह दी गई है। ये फसलें अपेक्षाकृत कम पानी में भी बेहतर उत्पादन देने में सक्षम मानी जाती हैं, जिससे किसानों का जोखिम कम हो सकता है।

जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में शुक्रवार को जशपुर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर रोहित व्यास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश पाटनवार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में जनजातीय समुदाय के कल्याण एवं विकास के लिए संचालित योजनाओं, शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं तथा आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की विभागवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान डॉ. आशा लकड़ा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनजातीय क्षेत्रों में संचालित सभी योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में कार्यों की प्रगति अपेक्षित नहीं है, वहां विशेष अभियान चलाकर कार्यों में तेजी लाई जाए।

बैठक की शुरुआत में उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संवैधानिक भूमिका एवं अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा कि आयोग को जांच के दौरान दीवानी न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त हैं। आयोग आवश्यक होने पर किसी भी अधिकारी या संबंधित व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, सार्वजनिक अभिलेख तलब कर सकता है तथा शिकायतों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर सकता है। उन्होंने कहा कि आयोग की अनुशंसाएं संबंधित विभागों की कार्रवाई रिपोर्ट के साथ संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती हैं, इसलिए प्रत्येक शिकायत एवं सुझाव पर गंभीरता से कार्रवाई आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, आंगनबाड़ी अथवा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय, शोषण अथवा अत्याचार की घटना सामने आती है, तो आयोग ऐसे मामलों में त्वरित हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करता है। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान डॉ. लकड़ा ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद, वाद-विवाद, सांस्कृतिक एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों के नियमित आयोजन पर बल दिया। उन्होंने विद्यालयों के नियमित निरीक्षण तथा सभी बालिका छात्रावासों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर रोहित व्यास ने जिले में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 400 से अधिक स्मार्ट क्लास संचालित हैं।

रायपुर में होगा राष्ट्रीय 'साइंस म्यूजियम' का आयोजन

विज्ञान भवन बनेगा अनुसंधान और नवाचार का आधुनिक केंद्रः प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा

प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण, आईएसओ प्रमाणन, साइंस सिटी और दो वर्षीय कार्ययोजना बनाने दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विज्ञान एवं अनुसंधान गतिविधियों को नई दिशा देने की पहल के तहत प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने रायपुर स्थित विज्ञान केन्द्र का निरीक्षण कर छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सीजी कॉस्ट) की केंद्रीय प्रयोगशाला सुविधा का जायजा लिया। उन्होंने प्रयोगशालाओं, तकनीकी इकाइयों एवं अन्य वैज्ञानिक सुविधाओं का अवलोकन करते हुए उनके आधुनिकीकरण, संसाधनों के विस्तार तथा गुणवत्ता उन्नयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में संभावित आगामी माह दिसम्बर में राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय साइंस म्यूजियम का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। गौरतलब है कि इस राष्ट्रीय आयोजन में देशभर के साइंस सेंटर हिस्सा लेंगे।

निरीक्षण के बाद आयोजित समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव श्री बोरा ने परिषद की सभी शाखाओं एवं प्रयोगशालाओं के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विज्ञान केन्द्र की लाइब्रेरी को आधुनिक एवं सुव्यवस्थित बनाने, प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित करने तथा शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विज्ञान केन्द्र को राज्य में विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार का उत्कृष्ट केंद्र बनाने के लिए दीर्घकालीन योजना के साथ कार्य किया जाए। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने इस मौके पर विज्ञान केन्द्र परिसर में वृक्षारोपण भी किया।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने निर्देश दिए कि परिषद की वैज्ञानिक सुविधाओं का लाभ केवल परिषद तक सीमित न रहे, बल्कि शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शोधार्थियों तथा विद्यार्थियों को भी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने उपलब्ध संसाधनों की व्यापक समीक्षा कर उन्हें अधिक उपयोगी एवं सुलभ बनाने तथा युवाओं को विज्ञान गतिविधियों से जोड़ने के लिए विज्ञान केंद्रों की गतिविधियों का सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया।

उन्होंने विज्ञान भवन में आवश्यक अधोसंरचना एवं गुणवत्ता मानकों का विकास कर शीघ्र आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिषद में संचालित जीआईएस आधारित प्रणाली के कार्यों की सराहना की तथा डीजीपीएस आधारित मैप निर्माण की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की।

प्रमुख सचिव ने परिषद की सभी शाखाओं एवं प्रयोगशालाओं के प्रभारियों को आगामी दो वर्षों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रस्तावित साइंस सिटी परियोजना की तैयारियों में तेजी लाने, आवश्यक मानव संसाधन विकसित करने, नए पदों के सृजन एवं भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने विज्ञान केन्द्र में उपलब्ध वैज्ञानिक उपकरणों एवं भवनों के नियमित रखरखाव और मरम्मत के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र के बेहतर संचालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित समीक्षा की जाएगी।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर एवं सीजी कॉस्ट के महानिदेशक प्रशांत कवीश्वर, डॉ. शिरीष कुमार सिंह, डॉ. अमित मेश्राम, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. अमित राम, सुश्री प्रज्ञा कदम, डॉ. वसीम रजा, क्यूरेटर प्रदीप कुर्रे सहित परिषद के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पीएम जनमन आवास योजना से पीव्हीटीजी परिवारों को मिल रहा सुरक्षित आवास

रायपुर। प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों को विभिन्न प्रकार की शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। पीएम जनमन आवास योजना विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के जीवन में न केवल सुधार ला रहा है, बल्कि पक्के मकान के सपनों को भी साकार कर रहा है। बलरामपुर जिले के विकासखंड राजपुर के ग्राम पंचायत चांची के निवासी श्री एतवा राम ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ वर्षों से कच्चे मकान में रह रहे थे। उनका परिवार रोजी मजदूरी कर जीवन यापन करता है। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण पक्का मकान बनाना उनके लिए चुनौती था।

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

बीमा पॉलिसी रिफंड के नाम पर 1.60 करोड़ की ठगी का खुलासा, दिल्ली से 3 आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। बीमा लोकपाल बनकर बीमा पॉलिसी की राशि रिफंड कराने का झांसा देकर पीड़ित से लगभग 1 करोड़ 60 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले 03 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान साइबर टीम ने बैंक खाताधारकों एवं नेटवर्क से जुड़े आरोपियों की पहचान कर ट्रांजिट रिमांड पर गिरफ्तार कर दुर्ग लाया। आरोपियों के कब्जे से 6 बैंक पासबुक, 4 चेकबुक, 3 मोबाइल फोन एवं विभिन्न सिम कार्ड जब्त किए गए, जिनका उपयोग साइबर ठगी में किया जा रहा था। जांच में आरोपियों के बैंक खातों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन पाए गए हैं तथा विभिन्न राज्यों में इनके विरुद्ध साइबर ठगी संबंधी शिकायतें दर्ज होना भी पाया गया है।

दरअसल रेंज साइबर थाना दुर्ग में पंजीबद्ध धारा 318(2), 318(4), 336(3) बीएनएस एवं 66-डी आईटी एक्ट के प्रकरण में आरोपियों द्वारा स्वयं को बीमा लोकपाल का अधिकारी बताकर बीमा पॉलिसी की राशि रिफंड कराने का झांसा दिया गया। आरोपियों ने पीड़ित से विभिन्न बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराकर कुल लगभग 1 करोड़ 60 लाख की साइबर ठगी की। प्रकरण की विवेचना के दौरान पूर्व में एक बैंक खाताधारक को गिरफ्तार किया गया था। तकनीकी साक्ष्यों एवं बैंक खातों के विश्लेषण के आधार पर विशेष टीम दिल्ली रवाना की गई।

टीम द्वारा आरोपी मनमीत सिंह, अमनदीप सिंह एवं ईशांत माहे उर्फ ईशु को चिन्हित कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने पैसों के लालच में बैंक खाते खुलवाकर उन्हें साइबर ठगी में उपयोग हेतु उपलब्ध कराना स्वीकार किया। जांच में यह भी सामने आया कि इन बैंक खातों का उपयोग एक विदेशी (नाइजीरियन) साइबर ठगी नेटवर्क द्वारा किया जा रहा था। आरोपियों को दिल्ली से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय, तीस हजारी, दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया तथा रेंज साइबर थाना दुर्ग लाया गया। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक विवेचना जारी है।

उक्त कार्यवाही में रेंज साइबर थाना दुर्ग की टीम के उप पुलिस अधीक्षक डॉ. चित्रा वर्मा, निरीक्षक पुष्पेन्द्र भट्ट, सहायक उप निरीक्षक यशवंत श्रीवास्तव, आरक्षक सुरेन्द्र कटरे, आरक्षक आवेश खान, आरक्षक कामेश्वर देशमुख एवं आरक्षक विक्रम सिंह राजपूत की सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि बीमा पॉलिसी रिफंड, केवाईसी अपडेट, निवेश अथवा किसी भी प्रकार के ऑनलाइन भुगतान संबंधी कॉल अथवा संदेश प्राप्त होने पर बिना सत्यापन किसी भी बैंक खाते में राशि हस्तांतरित न करें। किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल 1930 हेल्पलाइन अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं तथा निकटतम साइबर थाना से संपर्क करें।

खास खबर

नशे में बस चला रहा था चालक, डिक्की से 11 बकरियां बरामद

कोरबा। जिले के पसान थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने एक यात्री बस को जब्त कर बड़ी कार्रवाई की। जांच में बस चालक शराब के नशे में वाहन चलाते मिला, जबकि बस की डिक्की से 11 बकरियां अमानवीय तरीके से ठूंसकर ले जाते हुए बरामद की गईं। पेंड्रा से कोरबा जा रही जय श्री बस सर्विस को रोककर जांच की गई। चालक का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराने पर उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। बस में सवार यात्रियों ने भी चालक पर तेज रफ्तार और लापरवाही से बस चलाने की शिकायत की। जांच के दौरान बस की डिक्की से 11 बकरियां अमानवीय तरीके से भरी हुई मिलीं। पूछताछ में पता चला कि एक यात्री इन्हें अवैध रूप से परिवहन कर रहा था और इसके लिए अलग से किराया भी दिया गया था। पुलिस ने चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं अवैध पशु परिवहन एवं पशु क्रूरता से संबंधित प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी एएसआई चंद्रपाल खांडे ने बताया कि सड़क सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए वाहन जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

रायपुर में धोखाधड़ी, वाहन चोरी, गांजा तस्करी समेत कई मामले दर्ज

रायपुर। रायपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शुक्रवार को धोखाधड़ी, वाहन चोरी, अमानत में खयानत और मादक पदार्थ तस्करी के कई मामले दर्ज किए गए। पुलिस के अनुसार भुवन दास माणिकपुरी ने शिकायत में बताया कि जमीन की खरीदी-बिक्री का काम करने वाले आरोपी ने जमीन दिलाने का झांसा देकर उससे 7.50 लाख रुपये ले लिए, लेकिन न तो जमीन दिलाई और न ही रकम लौटाई। मामले में बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मोवा थाना क्षेत्र के दुबे कॉलोनी से अज्ञात चोर ने घर के बाहर खड़ी हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल चोरी कर ली। वाहन की कीमत करीब 20 हजार रुपये बताई गई है। वहीं सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कटोरा तालाब स्थित मेडिकल दुकान और वाइन शॉप के बीच से एक एक्टिवा चोरी हो गई, जिसकी कीमत करीब 15 हजार रुपये है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में भाठागांव स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के सामने से फैशन प्रो मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला दर्ज किया गया है। वहीं टिकरापारा थाना क्षेत्र में भाठागांव बस स्टैंड से होंडा शाइन मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। दोनों मामलों में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोवा थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धतका रोड कांपा क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पिट्ठू बैग में रखे 4 किलो 180 ग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स अधिनियम की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया।

भीमभौरी में अवैध वृक्ष कटाई पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रेंगाखार तहसील के ग्राम भीमभौरी में आम के पेड़ों की अवैध कटाई और लकड़ी के अवैध परिवहन के मामले में जिला प्रशासन ने त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। राजस्व, वन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए लकड़ी से भरा एक ट्रक और एक क्रेन जब्त कर पुलिस की सुपुर्दगी में सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार, नायब तहसीलदार प्रेमनारायण साहू को ग्राम भीमभौरी में अवैध वृक्ष कटाई की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वे राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान खसरा क्रमांक 108 में 12 आम के पेड़ अवैध रूप से कटे हुए पाए गए। कटी हुई लकड़ी को परिवहन के लिए तैयार किया जा रहा था।

फर्जी वन मुहर का किया गया इस्तेमाल

निरीक्षण के दौरान लकड़ी पर वन विभाग की मुहर लगी दिखाई दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग को बुलाया गया। मौके पर पहुंचे डिप्टी रेंजर भूपेंद्र कुमार ने जांच की, जिसमें यह मुहर फर्जी पाई गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अवैध लकड़ी को वैध दिखाने के लिए वन विभाग की नकली सील का उपयोग किया गया था।

मध्य प्रदेश भेजी जा रही थी लकड़ी

प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला कि कटे हुए आम के लट्ठों को मध्य प्रदेश के इंदौर भेजने की तैयारी थी। प्रशासन की समय पर कार्रवाई से अवैध परिवहन को रोक दिया गया। वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार कर जब्ती की कार्रवाई की गई। मामले की विस्तृत जांच जारी है। अवैध वृक्ष कटाई, फर्जी सील के उपयोग और लकड़ी तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और अवैध वृक्ष कटाई तथा लकड़ी तस्करी पर रोक लगाने के लिए आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

दो पत्नियों का विवाद, दूसरी पत्नी ने पहली को जिंदा जलाने का किया प्रयास, तीन आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति की दो पत्नियों का विवाद ऐसा बढ़ा कि दूसरी ने पहली पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली। इस मामले में शीतल वर्मा (22) निवासी पीएम आवास, खम्हरिया, चौकी स्मृति नगर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई है। शीतल वर्मा ने बताया कि एक जुलाई को परी खान के साथ लक्की सरदार को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद 2 जुलाई को परी खान ने अपने पति लक्की सरदार, बहन मुस्कान तथा जीजा राहुल यादव के साथ मिलकर रात लगभग 8:00 बजे उसके घर पहुंचे।

उसके साथ मारपीट कर ज्वलनशील पदार्थ डालकर हत्या करने का प्रयास किया। पीड़िता किसी प्रकार वहां से भागकर अपनी जान बचाई। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 940/2026 धारा 109, 296, 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस की जांच में सामने आया कि शीतल वर्मा लक्की सरदार की पहली पत्नी है। कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। शीतल मायके चली गई थी। दहेज और पैसों के विवाद में मामला पुलिस तक पहुंचा था। इसके बाद दोनों अलग हो गए। साल 2025 में लक्की ने मुझ से प्रेम विवाह कर लिया और हम दोनों खम्हरिया इलाके में रहने लगे। परी खान का कहना है कि उसने शीतल को अपने पति से विवाद नहीं करने के लिए कहा था, लेकिन इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। दूसरी पत्नी परी खान के साथ वर्चस्व को लेकर विवाद हुआ। विवाद से नाराज होकर परी खान ने अपने पति लक्की सरदार, बहन मुस्कान और जीजा राहुल यादव के साथ मिलकर पीड़िता की हत्या करने की साजिश रची।

2 जुलाई की रात लगभग 8 बजे सभी आरोपी ज्वलनशील पदार्थ लेकर पीड़िता के घर पहुंचे। उसके साथ मारपीट की। फिर उसके ऊपर और घर में ज्वलनशील पदार्थ डालकर हत्या करने का प्रयास किया। पीड़िता ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के फरार होकर नागपुर जाने की संभावना पर तत्काल पतासाजी की गई। आरोपी परी खान, मुस्कान एवं राहुल यादव को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मुख्य आरोपी लक्की सरदार की तलाश जारी है।

उक्त कार्रवाई में उप निरीक्षक दीपक सिंह चौहान, सहायक उप निरीक्षक उत्तम कुमार साहू, आरक्षक सविंदर सिंह, हर्षित शुक्ला, कमल नारायण तथा महिला आरक्षक मीरा वर्मा एवं मधुबाला की सराहनीय भूमिका रही। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान कानून सम्मत तरीके से करें। कानून अपने हाथ में लेने अथवा हिंसक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

कॉन्स्टेबल ने शादी का झांसा देकर युवती से किया रेप

3 साल तक बनाए संबंध, शादी की बात पर बोला- 2 बच्चे का पिता हूं

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक आरक्षक ने युवती से पहले दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर 3 साल तक शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो उसने खुद को पहले से शादीशुदा बताया और उसे धमकाने लगा।

युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 2023 में 22 वर्षीय युवती की पहचान सोशल मीडिया के जरिए तखतपुर में पदस्थ आरक्षक सुमंत मिरी से हुई थी। बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। आरोप है कि आरक्षक ने शादी का वादा कर युवती के साथ दुष्कर्म किया और करीब तीन साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान वह लगातार शादी का भरोसा देता रहा।

ट्रांसफर होने के बाद भी नहीं छोड़ा साथ

युवती ने पुलिस को बताया कि आरक्षक का ट्रांसफर बिलासपुर पुलिस लाइन होने के बाद भी वह उससे मिलने आता था और हर बार शादी का भरोसा देता था। लेकिन जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने शादी से इनकार कर दिया। आरोप है कि इसके बाद आरक्षक ने युवती को धमकाना शुरू कर दिया और उससे दूरी बनाने लगा। परेशान होकर युवती ने तखतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

शादीशुदा और दो बच्चे का पिता है आरक्षक

युवती ने शिकायत में बताया कि आरक्षक सुमंत मिरी पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। उसने यह बात उससे छिपाकर रखी थी। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया, तब उसने अपनी शादी और बच्चों की जानकारी दी।

सच्चाई सामने आने के बाद आरोपी ने युवती को धमकाना शुरू कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, पुलिस विभाग उसके खिलाफ विभागीय जांच और निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू कर रहा है।

करेंट से चिपककर पिता पुत्र की मौत

कवर्धा। जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए खेतों में बिछाए जा रहे अवैध विद्युत झटका तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुए। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बीरनपुर कला में गुरुवार सुबह एक हृदयविदारक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। मिली जानकारी के अनुसार, दोनों पिता-पुत्र सुबह धान की बुआई के लिए खेत पहुंचे थे। खेत के चारों ओर जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए झटका तार लगाया गया था। लगातार बारिश के कारण खेत में पानी भरा हुआ था, जिससे करंट का खतरा और बढ़ गया। काम के दौरान अचानक परमेश पटेल करंट की चपेट में आ गए। बेटे को तड़पता देख पिता गोकरण पटेल उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन वे भी करंट की चपेट में आ गए। जब तक आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, तब तक दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खण्ड-बेमेतरा (छ.ग.)

Gov.mail : eeprobem.phe-cg@nic.in

ऑनलाईन पद्धति से निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से प्रपत्र 'ए' में प्रतिशत दर पर जिला-बेमेतरा के विकासखंड बेमेतरा एवं नवागढ़ के अंतर्गत क्रमशः बेमेतरा समूह जल प्रदाय योजना (57 ग्राम) एवं नवागढ़ समूह जल प्रदाय योजना (54 ग्राम) के संचालन-संधारण कार्य हेतु रॉ वाटर एवं क्लीयर वॉटर पंम्पिंग मेन एवं ग्रेव्हिटी मेन 100 मिमी. से 350 मिमी. के अंतर्गत डी.आई. के.-7 एवं के.-9 पाईप लाईन का सुधार कार्य की निविदा हेतु ऑनलाईन पद्धति से निविदा आमंत्रित की गई है:-

क्र.	सिस्टम क्रमांक	नि.आ.सू. क्र. एवं दिनांक	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत (रू. लाख में)
01	194688	01/01.07.2026	विकासखंड बेमेतरा स.ज.प्र. योजना के 57 ग्रामों हेतु	27.57
02	194691	02/01.07.2026	विकासखंड नवागढ़ स.ज.प्र. योजना के 54 ग्रामों हेतु	28.35

1. बिड प्रारंभ की तिथि - 10.07.2026
2. बिड सबमिशन की अंतिम तिथि - 24.07.2026

उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा, विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज एवं अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब-पोर्टल http://eprocurement.cgstate.gov.in में दिनांक 10.07.2026 में देखी जा सकती हैं।

जी-262701877/4

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खण्ड
बेमेतरा (छ.ग.)

बॉयफ्रेंड को पैसों की जरूरत पड़ी तो गर्लफ्रेंड बनी चोर, दोनों गिरफ्तार

2 साल से जिस घर में रही, वहीं से उड़ाए 24 हजार रुपए

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। बॉयफ्रेंड को पैसों की जरूरत थी। उसने मदद मांगी तो गर्लफ्रेंड ने ऐसा रास्ता चुना, जिसने उसे सीधे जेल पहुंचा दिया। जिस परिवार ने दो साल तक उसे अपने घर में रखा, भरोसा किया और घर की जिम्मेदारी सौंपी। उसी घर से उसने शादी की भागदौड़ का फायदा उठाकर पैसे चोरी कर लिए। मामला दुर्ग के सुपेला थाना क्षेत्र का है।

पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी महिला ममता चौहान और उसके बॉयफ्रेंड शीतल वर्मा को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से चोरी की कैश और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं।

पुलिस की पूछताछ में जो वजह सामने आई, उसने पुलिस को भी चौंका दिया। ममता ने बताया कि उसके प्रेमी शीतल वर्मा को पैसों की जरूरत थी। उसी के कहने पर उसने चोरी की साजिश रची। शादी की भीड़-भाड़ के बीच अलमारी से कैश निकाल ली। पुलिस का कहना है कि चोरी के लिए प्रेमी ने ही उसे उकसाया था।

दो साल से घर में कर रही थी काम

सूर्या विहार कॉलोनी जुनवानी निवासी रोहन कुखरानिया ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि साल 2024 में अपनी वृद्ध मां की देखभाल के लिए लाइफ होम केयर सर्विस के जरिए ममता चौहान को केयरटेकर रखा गया था।

मां के निधन के बाद भी ममता घर में रहकर घरेलू काम करती रही। करीब दो साल तक परिवार के साथ रहने के कारण उसे घर की पूरी व्यवस्था, अलमारी और उसमें रखे पैसों की जानकारी थी।

भतीजी की शादी में व्यस्त था परिवार

26 और 27 जून 2026 को घर में भतीजी की शादी थी। पूरा परिवार शादी के कार्यक्रम में व्यस्त था। इसी दौरान ममता ने मौका देखकर अलमारी में रखे 24 हजार रुपए निकाल लिए। चोरी के बाद वह बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। जब परिवार को पैसों की जरूरत पड़ी और अलमारी देखी गई तो कैश गायब मिली।

इसके बाद सुपेला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी महिला के मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच की। लोकेशन के आधार पर पुलिस रायपुर पहुंची, जहां ममता अपने प्रेमी शीतल वर्मा के साथ मिली। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

पैसे और मोबाइल पुलिस ने किया जब्त

पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 23 हजार 500 रुपए कैश और दो मोबाइल बरामद किए हैं। जब्त सामान की कुल कीमत 43 हजार 500 रुपए है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

अवैध शराब बेचते आरोपी गिरफ्तार, 30 पौवा देशी शराब जब्त

दुर्ग। उतई थाना क्षेत्र में अवैध शराब बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 पौवा देशी प्लेन शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 3 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार, 2 जुलाई 2026 को थाना उतई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उतई स्थित बिजली कार्यालय के पीछे एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री कर रहा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम देवराज यादव उर्फ छोटू, निवासी मीलपारा, उतई, जिला दुर्ग बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक प्लास्टिक थैले में रखी 30 पौवा देशी प्लेन शराब बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया।

सहकारिता से बढ़ेगी किसानों की आय, विकसित छत्तीसगढ़ की नींव होगी मजबूत : मुख्यमंत्री

- 162 करोड़ से अधिक की तेंदूपत्ता प्रोत्साहन राशि वितरण का शुभारंभ, 1352 नई सहकारी समितियों के गठन से सहकार का विस्तार
- पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वनोपज, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में भी सहकारिता को मिल रहा है बढ़ावा
- किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है सहकारिता
- उत्कृष्ट सहकारी समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार से किया गया सम्मानित, महिला स्व सहायता समूह को वितरित किया गया लाभांश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय का गठन देश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह निर्णय 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को साकार करने वाला है। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में सहकारिता के माध्यम से किसानों, वनवासियों, महिला समूहों और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन एवं सहकारी सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर उत्कृष्ट समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किया तथा संग्रहण वर्ष 2023 के 7.14 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 162 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि के वितरण का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और बचपन से ही सहकारिता से मेरा गहरा रिश्ता रहा है। तभी से मुझे विश्वास था कि सहकारिता के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' का वही सपना धरातल पर साकार होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल में उन्हें राज्यमंत्री के रूप में साथ काम करने का अवसर मिला और उन्होंने किसानों के प्रति प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता तथा समर्पण को बहुत करीब से देखा है।

किसानों के कल्याण के प्रति इसी प्रतिबद्धता के कारण प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाते हुए उसका नाम 'कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय' किया, ताकि किसानों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता बने। सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिली है और इसका लाभ सीधे किसानों एवं ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार केवल कृषि ही नहीं बल्कि पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वनोपज, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में भी सहकारिता को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। राज्य सरकार पशुपालन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पहले किसानों को खेती-किसानी के लिए 16 से 18 प्रतिशत दर पर ऋण लेना पड़ता था और भारी-भरकम ब्याज का बोझ उन्हें आर्थिक रूप से परेशान कर देता था। आज सहकारिता व्यवस्था और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने सहकारिता से जुड़े विभिन्न स्टालों का किया अवलोकन व निरीक्षण

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया और सहकारिता के माध्यम से किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों तथा वनधन समितियों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की सराहना की। उन्होंने हरित क्रांति आदिवासी सहकारी समिति जशपुर, महामाया बहुउद्देशीय सहकारी समिति कोरबा, बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम, छत्तीसगढ़ हर्बल्स, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड), छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, इफ्को तथा गंगा मैया दुग्ध उत्पादक संघ बालोद सहित विभिन्न संस्थाओं के स्टॉलों का अवलोकन कर उनके कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 5 नवीन पैक्स समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित किए तथा छत्तीसगढ़ हर्बल्स के पांच नए उत्पादों का लोकार्पण किया। उन्होंने उत्कृष्ट तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए, वन-धन समितियों की हैंडबुक का विमोचन किया, महिला स्व-सहायता समूहों को लाभांश वितरित किया तथा विभिन्न हितग्राहियों को सामग्री, प्रोत्साहन राशि और केसीसी ऋण वितरित किए। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सहकारिता का मूल उद्देश्य है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के 15 लाख से अधिक किसानों को 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिससे किसानों को खेती के लिए सुलभ वित्तीय सहायता मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिस प्रकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व और सुरक्षा बलों के साहस से नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता मिली है, उसी प्रकार सहकारिता के माध्यम से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन लाया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सहकारी सप्ताह के दौरान विषय विशेषज्ञों के मंथन से प्रदेश में सहकारिता के नए आयाम स्थापित होंगे और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा।

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पांच वर्ष पूरे होना देश के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर 29 जून से 06 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सहकारिता का मूल उद्देश्य है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की कोई भी पंचायत सहकारिता से वंचित न रहे, इस दिशा में कार्य करते हुए राज्य में 1352 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने सहकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से किसानों का पंजीयन पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से किया जा सकेगा।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी केदारनाथ गुप्ता, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, प्राधिकृत अधिकारी विपणन संघ शशिकांत द्विवेदी, सहकार भारती के कनिराम, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी सौरभ शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार बेसरा, छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ के अध्यक्ष भोजराम देवांगन, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्षगण, सहकारिता सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता रमेश शर्मा सहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी, किसान एवं बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर प्रदेश में पर्याप्त रासायनिक खाद उपलब्ध

किसानों को नहीं होगी डीएपी की कमी, माह जुलाई में 46,500 टन डीएपी सप्लाई की आपूर्ति प्राप्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराने के अपने संकल्प पर लगातार प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। खरीफ वर्ष 2026 के लिए 30 जून तक की स्थिति में 13 लाख 16 हजार 506 मीट्रिक टन उर्वरकों का भण्डारण किया जा चुका है।

यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की पहल पर छत्तीसगढ़ को माह जुलाई में 46,500 टन डीएपी सप्लाई की आपूर्ति प्राप्त हुई है, जो सामान्य से अधिक है। इससे अब किसानों के लिए पर्याप्त डीएपी उपलब्ध हो सकेगा। बता दें कि अब तक भंडारित कुल रासायनिक खाद पिछले साल इसी अवधि में भंडारित रासायनिक खाद की तुलना में 1.08 लाख मीट्रिक टन अधिक है।

वहीं प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों के भण्डारण और वितरण की स्थिति यह दर्शाती है कि सरकार ने खेती के मौसम से पहले ही किसानों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराना केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि किसान परिवारों की समृद्धि और प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बता दें कि केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए खरीफ वर्ष 2026 में 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध 30 जून की स्थिति में 13 लाख 16 हजार 506 मीट्रिक टन उर्वरकों का भण्डारण किया जा चुका है। इनमें यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी तथा एसएसपी जैसे सभी प्रमुख उर्वरक शामिल हैं। यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि किसानों को बुआई के दौरान खाद की उपलब्धता में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए सरकार ने पहले से व्यापक तैयारी की है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के किसानों को अभी तक 7 लाख 27 हजार 833 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है। यह वितरण किसानों की वास्तविक मांग के अनुरूप लगातार किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में 5 लाख 88 हजार 673 मीट्रिक टन उर्वरकों का शेष भण्डार उपलब्ध है, जिससे आगामी दिनों में भी किसानों को निर्बाध रूप से खाद उपलब्ध कराई जा सकेगी। यदि गत वर्ष की समान अवधि से तुलना करें तो इस वर्ष की उपलब्धियां और भी उत्साहजनक हैं।

महतारी वंदन योजना से बढ़ा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर बनीं सुनीता श्रीवास

सक्ती। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना जिले की हजारों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली सहायता राशि महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ा रही है। विकासखंड सक्ती अंतर्गत ग्राम किरारी निवासी सुनीता श्रीवास इसकी प्रेरणादायक मिसाल हैं। वे बताती हैं कि पहले छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि उनके लिए महत्वपूर्ण सहारा बन गई है। बच्चों के पालन-पोषण में भी सहयोग कर पा रही हैं।

सरकार गांव, गरीब और किसानों की तरक्की के लिए प्रतिबद्धः मंत्री टंक राम वर्मा

राजस्व मंत्री ने ग्राम झोंका को दी विकास कार्यों की सौगात, 27 लाख रुपए से अधिक की नई घोषणाएं

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्य सरकार ग्रामीण अंचलों के चहुंमुखी विकास और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम पंचायत झोंका में विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने यहाँ विभिन्न जनकल्याणकारी और विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर क्षेत्र के विकास को और गति देने के लिए 27 लाख रुपये से अधिक की नई विकास योजनाओं की घोषणा भी की।

ग्राम झोंका में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्व मंत्री वर्मा ने महामाया मंदिर सामुदायिक भवन, केश डबरी प्रवेश द्वार, पचरी निर्माण, महतारी सदन, मुक्तिधाम शेड, तालाब गहरीकरण तथा रंगमंच भवन सहित विभिन्न अधोसंरचना कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने कुर्मी पारा में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण कर उसे आम जनता को समर्पित किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गांव, गरीब और किसानों की तरक्की के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना हमारी प्राथमिकता है ताकि ग्रामीणों का जीवन स्तर और बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में राशि की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।

इन महत्वपूर्ण कार्यों की हुई घोषणा: ग्रामीणों की पुरजोर मांग और क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए राजस्व मंत्री ने कार्यक्रम के मंच से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं,जिसमे प्राथमिक शाला में सुलभ शौचालय निर्माण हेतु 2 लाख रुपये, छापड़ तालाब के गहरीकरण के लिए 10 लाख रुपये, मुक्तिधाम में शेड निर्माण के लिए 7 लाख रुपये, तालाबों में पचरी निर्माण के लिए 3 लाख रुपये और सामुदायिक भवन एवं ज्योति कक्ष निर्माण हेतु 5 लाख रुपये देने का ऐलान किया। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए उन्होंने जागृति महिला मंडल को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि देने की भी सहर्ष घोषणा की। जिला पंचायत अध्यक्ष, बलौदाबाजार जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत झोंका के सरपंच हरीराम ध्रुव सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक व ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

अल्प वर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री साय ने खरीफ-2026 एवं संभावित अल्प वर्षा की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने निवास कार्यालय में खरीफसीजन-2026 के दौरान संभावित अल्प वर्षा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग तथा विकसित भारत-बीवी-जी राम जी योजना की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में मौसम की संभावित स्थिति, खाद एवं बीज की उपलब्धता, जल संरक्षण, सिंचाई प्रबंधन, वैज्ञानिक खेती तथा ग्रामीण रोजगार से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और किसी भी परिस्थिति में उन्हें खाद, बीज, तकनीकी मार्गदर्शन अथवा आवश्यक संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करते हुए प्रत्येक जिले के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार रखें।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा से उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त डीएपी उर्वरक उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। इसके सकारात्मक परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ को 46 हजार टन से अधिक डीएपी की आपूर्ति प्राप्त हुई है, जो सामान्य से अधिक है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध होगा तथा खरीफ सीजन की तैयारियों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान की फसल के लिए आवश्यक सिंचाई जल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में जल स्रोतों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

उन्होंने कृषि विभाग को निर्देशित किया कि किसानों को कम एवं मध्यम अवधि में पकने वाली धान की किस्मों, डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर), कतार पद्धति से बुवाई, बीज उपचार, नमी संरक्षण तथा वैज्ञानिक खेती की आधुनिक तकनीकों के प्रति व्यापक रूप से जागरूक किया जाए। साथ ही उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में दलहन एवं तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, जिससे किसानों को बेहतर आय के अवसर प्राप्त हों और कृषि जोखिम कम हो।

मुख्यमंत्री साय ने किसानों से अपील की कि वे कृषि संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या अथवा तकनीकी सलाह के लिए कृषि महाविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों तथा कृषि विभाग के विशेषज्ञों से संपर्क करें और वैज्ञानिक खेती को अपनाएं। उन्होंने अमानक बीज एवं उर्वरकों की बिक्री तथा कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में बताया गया कि राज्य में खाद एवं बीज का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है तथा सभी जिलों में समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। बैठक में बताया गया कि अर्ली वेरायटी के धान बीज बीज निगम के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराने की संपूर्ण तैयारी पूरी कर ली गई है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संभावित अल्प वर्षा जैसी परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जल संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाया जाएगा। उन्होंने 'मोर गांव मोर पानी' अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए वर्षा जल संरक्षण, खेत तालाब, जल संरचनाओं के निर्माण तथा भूजल संवर्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आकाशीय बिजली जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की सुरक्षा के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विकसित 'सचेत', 'दामिनी' और 'मेघदूत' मोबाइल एप का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि समय पर मौसम संबंधी जानकारी किसानों तक पहुंच सके। साथ ही सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उचित दर पर खरपतवारनाशक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे उत्पादन लागत कम हो और फसल सुरक्षित रह सके।

बैठक में बताया गया कि 1 जुलाई 2026 से योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मजदूरी दर 300 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, जल सुरक्षा, जल संरचनाओं के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निर्देश दिए कि वीबी-जी राम जी योजना के माध्यम से ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, जिनसे एक ओर ग्रामीणों को निरंतर रोजगार प्राप्त हो और दूसरी ओर प्रदेश की जल सुरक्षा मजबूत हो। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में किया गया प्रत्येक प्रयास आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का आधार बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और ग्रामीण परिवारों के हितों की रक्षा, कृषि उत्पादन को सुरक्षित रखने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषि विश्वविद्यालय द्वारा नियमित रूप से जारी किए जाने वाले बुलेटिनों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक प्रभावी जनजागरूकता अभियान तैयार किया जाए, ताकि यह जानकारी किसानों तक जमीनी स्तर पर पहुँचे। साथ ही सोशल मीडिया एवं पारंपरिक मीडिया के माध्यम से भी इनका व्यापक प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950